हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 24 अगस्त 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

24/8/2018/1100/डी0सी0/एन0जी0-1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : श्री मुकेश अग्निहोत्री आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री - माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः हमने नियम 67 के अन्तर्गत आप को नोटिस दिये है। जिसमें मेरी ओर से, श्रीमती आशा कुमारी जी की ओर से और श्री रामलाल ठाकुर जी की ओर से नोटिस है। मैं उम्मीद करता हूॅ कि आपके सचिवालय द्वारा आपको नोटिस प्राप्त हो गया होगा।

अध्यक्ष - माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृप्या आप बैठ जाइये। आज दिनांक 24-08-2018 को प्रातः 9:45 बजे माननीय सदस्य श्री रामलाल ठाकुर, श्री मुकेश अग्निहोत्री व श्रीमती आशा कुमारी जी से नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं। जिसमें कानून व्यवस्था की बिगडती स्थिती, देवभूमि में लगातार हत्या व बलात्कार की जो घटनाऐं घटित हो रही हैं, नशा खासतौर पर सिनथैटिक ड्रग्स और माफिया राज्य में सरगर्म है, इसको लेकर के नियम 67 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त हुई है। मैने इन सूचनाओं को तत्काल सरकार को वस्तुस्थिती जानने हेतु प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार से विस्तृत उत्तर प्राप्त होगा, सम्बन्धित जो नियम है यानी जिस नियम के अन्तर्गत इसको लगाना होगा, लगाया जाऐगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री - अध्यक्ष महोदय, जब सरकार यहॉ बैठी है और नियम 67 के अन्तर्गत नोटिस है तो सारा काम रोककर के पहले इस पर बात करें। जब से मौजूदा सरकार बनी है और जिस ढ़ंग से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही है, यह बहुत ही निंदनीय मसला हो गया है।

24/8/2018/1100/डी0सी0/एन0जी0-2

अध्यक्ष-: मुकेश जी, मैने अभी आपको समय नहीं दिया है क्योंकि मैंने अभी आपका ईशु एलाउ नहीं किया है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री - अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है प्रदेश में पिछले 7 माह में 64 मर्डर हो गए है।

अध्यक्ष - मुकेश जी, मैने अभी आप को समय नहीं दिया है। जब आपका विषय आएगा और जब हम एलाउ करेंगे, तो आप चर्चा कर सकते हैं। …..(व्यवधान)……

अध्यक्ष - माननीय संसदीय कार्यमन्त्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी।

संसदीय कार्यमन्त्री - अध्यक्ष महोदय, जो अप्रोप्रिएट नियम है उसके अर्न्तगत विपक्ष जब भी यह चर्चा करना चाहे , करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नियम 67 के अन्तर्गत यह चर्चा करनी बनती नहीं है। इन्होनें नशे के बारे में कहा है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जो स्टैंड लिया है उसी स्टैंड ने आज 7 राज्य को इक्कठा कर नशे के विरूद्ध खडा किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमन्त्री जी को बधाई दी जानी चाहिए। …..(व्यवधान)……

अध्यक्ष - कृप्या आप बैठ जाइये। ठाकुर साहब आप भी बैठिये।

माननीय संसदीय मन्त्री : मुकेश जी एक मिनट मेरी बात सुन लिजिए। …..(व्यवधान)……

अध्यक्ष - मुकेश जी । मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलना. Not to be recorded.

श्री आर0जी0 द्वारा जारी……

24/08/2018/1105/RG/DC/1

---(**व्यवधान**)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जाएं, I am on leg. मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उसके पश्चात आप बोलिए। आप बैठिए ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हर तीसरे दिन ---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप बोलिए। जो नियम-67 का नोटिस प्राप्त हुआ है, मैंने उसको विस्तार से यहां पढ़ा है और अब मैं स्थगन प्रस्ताव के नियम को कोट करना चाहूंगा। Adjournment Motion Rule-69 ---(interruption)--- आप एक मिनट बैठ जाएं। आपको समय मिलेगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह 9.45 बजे का नोटिस है और आप कह रहे हैं कि हमने सरकार को भेजा है।

अध्यक्ष : मुकेश जी, आप निर्णय सुनिए, उसके बाद बोलिए, कृपया आप बैठिए। Rules and Procedures, Adjournment Motion Rule - 69(2) says 'not more than one matter shall be discussed on the same motion'. Adjournment Motion Rule -69 (9) says, 'the motion shall not raise any question which under the Constitution or these rules can only be raised on a distinct motion' and Adjournment Motion Rule -69 (7) says, 'the motion shall not deal with a matter on which resolution could not be moved'. आप मुझे सुनिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को संरक्षण देंगे!

अध्यक्ष : आप एक मिनट ठहरिए, मुझ पर आरोप मत लगाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कानून-व्यवस्था का मसला है।

24/08/2018/1105/RG/DC/2

अध्यक्ष : आप एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आप एक मिनट ठहरिए, मैं आपको समय दूंगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के नोटिस में सरकार को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष : : आप एक मिनट ठहरिए तो सही।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : हमने एक घण्टे पहले नोटिस दिया है।

अध्यक्ष : तो क्या हुआ? आप बैठिए, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्या आप नहीं सुनेंगे? You will have to listen to me, आप बैठिए। क्योंकि इस नोटिस में तीन विषय एक साथ दिए गए हैं और स्थगन प्रस्ताव इसके ऊपर नहीं लाया जा सकता है।---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, 'गुड़िया' हैल्पलाईन, 'शक्ति ऐप्प' सबकी-सब फ्लॉप हैं। कसौली में मर्डर हो गया, बद्दी में मर्डर हो गया, शिमला में 18 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ---(व्यवधान)---पालमपुर और मनाली में बलात्कार के मामले हुए हैं। ---(व्यवधान)---माइनर गर्ल्स से रेप हुआ है।---(व्यवधान)---

Smt Asha Kumari: Hon'ble Speaker, Sir, all these come under Law and Order. ---(interruption)---

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नोरेबाजी करने लगे।)

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू

24/08/2018/1110/MS/AG/1

.(व्यवधान).

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइए।

प्रश्नकाल आरम्भ।

स्थगित प्रश्न संख्याः 85

(**कांग्रेस पार्टी के** सभी **माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए सदन से बहिगर्मन कर गए**)

प्रश्न संख्याः 138 (श्री बलबीर सिंह वर्मा)

24/08/2018/1110/MS/AG/2
अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, सरकार हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है और आज नियम-67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आपके समक्ष रखा गया, उसमें आपने व्यवस्था दे दी और उस व्यवस्था में आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि यह नियम-67, नियमों के अनुसार नहीं है। क्योंकि नियमों में बड़ा स्पष्ट है कि नियम-67 का एक विषय हो सकता है। इसमें बहुत सारे विषयों को क्लब नहीं किया जा सकता। इन्होंने कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा मांगी, ड्रग्ज के इशू को भी उसमें जोड़ दिया, बलात्कार के मामलों को भी जोड़ दिया, हत्यायें और माफिया राज के मामलों को भी उसमें जोड़ दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इस दल की आज ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां इनका मार्ग-दर्शन करने वाला कोई नहीं रह गया है। वहां नियमों के अनुसार चलने की परम्परा पहले भी बहुत कम थी लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष के लोग चर्चा के लिए गम्भीर हैं तो इनमें से जिस विषय पर ये चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मेरी यह बड़ी स्पष्ट मान्यता है कि लोकतंत्र में चर्चा को कभी रोकना भी नहीं चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस चर्चा के विषय को लेकर के स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि उस चर्चा से क्या आप प्रदेश-हित

के लिए कोई विषय निकालना चाह रहे हैं या सिर्फ राजनैतिक मकसद के लिए चर्चा करना चाह रहे हैं। मुझे इनकी बातचीत से प्रदेश-हित का विषय कम दिख रहा है लेकिन राजनैतिक दृष्टि से उसमें से अपना मकसद निकालने की कोशिश ज्यादा हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि आज इनका यूथ की ओर से कोई प्रदर्शन भी है और उस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए और भाषण देने के लिए इन्होंने जाना है। हमें कोई आपत्ति नहीं है और विधान सभा के सत्र के दौरान इस तरह के प्रदर्शन करना लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार होता रहता है। पहले भी ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यदि आज हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए इस प्रकार का माहौल पैदा करके माननीय सदन के समय को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

24.08.2018/1115/जेके/एच0के/1

मुख्य मंत्रीः------जारी------

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इन विषयों पर चर्चा करनी है तो नियम है और नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों का अपना-अपना मत उसमें आ जाएगा। उसके अनुरूप फिर पता भी लग जाएगा कि उसके बाद वे कहां पर थे, वे कहां पर खड़े हैं और हम कहां पर हैं? उनके स्तर पर कौन से प्रयत्न हुए, कौन से प्रयास हुए और हमारी ओर से इन सात महीनों के कार्यकाल में क्या-क्या प्रयास हुए?

अध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं है कि इन्होंने वॉक आउट किया है या बिना वॉक आउट के ही चले गए हैं या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही चले गए लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इनसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि आओ और यदि आप नियमों के अनुसार चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम उसे स्वीकार करके चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश हित का कोई भी विषय,

यदि वह हित मजबूत होता है, प्रदेश हित में कोई भी बात आती है, उसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

24.08.2018/1115/जेके/एच0के/2

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष ने जो नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया है आपने उसमें व्यवस्था दी है उसमें जिस विषय पर रेज़ोल्यूशन सदन में आ सकता है, वह नियम-67 के अन्तर्गत उठाया नहीं जा सकता । इसमें सभी ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। किसी भी नियम के अन्तर्गत जैसे कि माननीय सदन के नेता ने कहा कि किसी भी विषय पर ये एप्रोप्रिएट रूल के अन्तर्गत कोई चर्चा लाएंगे तो हम उसके लिए सदैव तैयार हैं। सबसे प्रमुख विषय है ड्रग्ज़, जिसके बारे में इन्होंने कहा है और मैं तो समझता हूं कि ड्रग्ज़ के बारे में इस सदन को माननीय मुख्य मंत्री जी को कॉम्पिलमैंट करना चाहिए कि ये पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने इस विषय पर सारे उत्तरी भारत के मुख्य मंत्रियों को इकट्ठा किया है उसके लिए पंचकूला में एक नोडल ऑफिस खोला जा रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी लैवल पर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और सारे का सारा पुलिस डिपार्टमैंट इसमें सेन्सिटाइज़ है। लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए गुड़िया ऐप है, होशियार ऐप है, शक्ति बटन है और लॉ एण्ड ऑर्डर पूरे का पूरा चाक-चौबन्द है। इसके बावजूद भी अगर ये चर्चा करना चाहें नियम-130, नियम-117 या नियम-62 और 64 किसी में भी ये चर्चा करना चाहते हैं, यदि आज भी ये चर्चा करना चाहते हैं तो आज भी हम इस बात के लिए इसको कन्वर्ट करके तैयार हो सकते हैं। लेकिन इनको इस बात का भी ध्यान

रखना चाहिए कि चिट्टा, जिस नशे की बात ये कर रहे हैं वह चिट्टा कहां से आया? पिछले सदन में हम चर्चा करते रहे हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र को माननीय विपक्ष के नेता रिप्रेजैंट करते हैं, चिट्टा का ऑरिजिन ही हिमाचल प्रदेश में उस क्षेत्र से हो करके आया है। तो ये चर्चा का विषय है। इस पर हमको चर्चा करनी है और हम भी चाहते हैं कि ये चर्चा करें। यदि एप्रोप्रिएट नियम के अन्तर्गत चर्चा करेंगे तो जरूर हम तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस नियम

24.08.2018/1115/जेके/एच0के/3

का दुरूपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए हम इनकी तीव्र निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं क्योंकि यह वॉक आउट नहीं है, इसलिए वॉक आउट की भर्त्सना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन अभी इनको विपक्ष की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। ये ट्रेनिंग लेने बाहर गए हैं। ये जब ट्रेनिंग ले कर वापिस आ जाएं तो इस बात की हम उनसे अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्षः नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त हुआ। उस नोटिस के उत्तर में मैंने व्यवस्था दी। मैं यहां पर आज और एक विषय बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के द्वारा नियम-62 के अन्तर्गम 6 सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। आज भी उसमें से एक सूचना चर्चा के लिए लगी है। नियम-101 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं हैं, जो वीरवार को चर्चा के लिए लगी है और नियम-130 के अन्तर्गत अभी तक हमें 6 नोटिस प्राप्त हुए हैं,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2018/1120/SS-YK/1

मा0 अध्यक्ष क्रमागतः

जिसमें से एक चर्चा आज लगी है और शेष आने वाले दिनों में लगाए जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और ये सब सूचनाएं भी इन माननीय सदस्यों के द्वारा दी गई हैं। नियम-324 के अन्तर्गत भी अनेक मामले हमारे पास आए हैं। इसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का मामला और नशे का मामला अगर किसी अन्य नियम के अन्तर्गत आया होता तो शायद उसको स्वीकार करने में कोई देरी न की जाती और अभी भी यदि आयेगा तो उसके ऊपर हम गहनता के साथ विचार करेंगे।

पुनः प्रश्न काल प्रारम्भ।

24.08.2018/1120/SS-YK/2

प्रश्न संख्याः 138 (स्थगित)

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसके सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्पैशली मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के जो पुराने स्रोत थे वे मैक्सिमम बंद हो गए हैं। उसमें विशेष रूप से गर्मी के समय मई और जून महीने में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जितने भी हमारे नदी और नाले हैं वे मई और जून महीने में पूरी तरह से सूख जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सूचना सभापटल पर रखी है कि वे बहुत सारी योजनाएं केन्द्र सरकार से ला रहे हैं। इसमें जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है जैसे हमारे नदी और नाले मई और जून महीने में बिल्कुल सूख जाते हैं क्या वहां पर चैक डैम की ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को पानी मिल सके। इसमें जैसे इन्होंने एशियन डिवैल्पमैंट बैंक के तहत 708 करोड़ की स्कीम भेजी है क्या इसमें हमारे क्षेत्र को भी डालेंगे? जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उसमें 64 पंचायतें हैं। उन 64 पंचायतों में से 43 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पहाड़ी की ऊंचाई पर सारे गांव बसे हुए हैं। उसमें पानी को

रोकने के लिए क्या रेन हार्वैस्टिंग सिस्टम माननीय मंत्री महोदय डिवैल्प करेंगे? जैसे मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम फॉरैस्ट एरिया है --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप जल्दी से प्रश्न करिये।

श्री बलबीर सिंह वर्माः क्या उस फॉरैस्ट एरिया में माननीय मंत्री महोदय रेन हावैस्टिंग टैंक बनायेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 9516 पेयजल योजनाएं हैं। सिंचाई की 2669 परियोजनाएं हैं। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो कुल 12185 योजनाएं हैं। यह आंकड़ा आने वाले समय में घटेगा नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगा। माननीय सदस्य जी ने विशेष करके अपने चुनाव क्षेत्र की चिन्ता जाहिर की है। इनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पिछली बार जो गर्मी पड़ी, उस गर्मी के महीने में पूरे प्रदेश के अंदर हमारी 922 ऐसी पेयजल परियोजनाएं हैं जोकि 80 प्रतिशत से भी ज्यादा बंद हो गई हैं। 245 ऐसी सिंचाई की योजनाएं हैं जोकि 80 प्रतिशत से ज्यादा बंद हो गईं।

24.08.2018/1120/SS-YK/3

कुल मिलाकर ऐसी 1167 योजनाएं हैं। चौपाल विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर नेरवा मंडल में विशेष करके 12 ऐसी बहाव पेयजल परियोजनाएं हैं जिनका 80 से 90 प्रतिशत के बीच स्त्रोस सूख गया और

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2018/1125/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्याः 138 जारी----

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी---

उसकी वजह से वहां पानी की तकलीफ़ हुई। इन सारी दिक्कतों को देखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे प्रदेश के लिए अनेकों ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएं लाई हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जैसे-जैसे जो योजना आई, उसके बारे में प्रैस कॉफ्रैंस की है और मुझे लगता है कि इस सत्र के दौरान भी मुख्य मंत्री जी उन योजनाओं के बारे में यहां पर कोई न कोई प्रस्ताव रखेंगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर विशेषकर चौपाल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना आपको ब्रिक्स में दी है जो कि दो विधान सभा चुनाव क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी 1 उसमें ठियोग विधान सभा चुनाव क्षेत्र की भी 8-9 पंचायतें हैं और आपके विधान सभा चुनाव क्षेत्र की भी पंचायतें हैं। इसके अलावा क्योंकि एक क्षेत्र तो आपकी तरफ पड़ता है लेकिन जो दूसरी तरफ का क्षेत्र है, जिसकी आप बहुत ज्यादा चिन्ता कर रहे हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगें और मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करुंगा कि चौपाल विधान सभा चुनाव क्षेत्र, जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है, हम वहां के पी0सी0 हेबिटेशन्ज़ को आधार मान कर कोई नई योजना उस तरफ आपको दें ताकि जो वहां पर आपकी 12 छोटी योजनाएं हैं, उनके कार्यक्षेत्र के बीच में वह न आए और आपके पीने के पानी की दिक्कत का समाधान किया जा सके।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि ब्रिक्स में 75 करोड़ रु0 के करीब मेरे चुनाव क्षेत्र और ठियोग चुनाव क्षेत्र के लिए योजनाओं की डी0पी0आर0 बन रही है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि एशियन डवैल्पमैंट बैंक के माध्यम से लगभग 708 करोड़ रु0 की परियोजना, जिसमें मेरा चुनाव क्षेत्र ऐड नहीं है, क्या चौपाल क्षेत्र को भी इसमें ऐड करेंगें? दूसरे, जो रेन वाटर

24.08.2018/1125/केएस/वाईके/2

हार्वेस्टिंग सिस्टम है, विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में थिक फोरैस्ट एरिया है, उसमें क्या फोरैस्ट लैंड में भी आप रेन हार्वेस्टिंग करेंगें और इसके लिए बड़े तालाब बनवाएंगें?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश के लिए लाई है। जिस 708 करोड़ रु0 की योजना की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, कोई भी योजना भारत सरकार से आती है जो फॉरन फंडिंग होती है वह राशि कोई एक मुश्त भारत सरकार या जो भी फॉरन फंडिंग एजैंन्सिज़ हैं, वह एक मुश्त आपको राशि भेज देती हैं। बड़ी योजनाएं होती है, बड़ी योजनाओं में वह राशि फेज़्ड मैनर में किसी भी प्रदेश को उस योजना के लिए देते हैं। उस योजना में माननीय सदस्य जी को यह गलत फ़हमी है कि उसमें इनके चुनाव क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। यह योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए लाई है और हो सकता है कि सोमवार को माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटमैंट दे। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत ज्यादा विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं और जहां उपयुक्त स्थान पाए जाएंगे, वे सारे के सारे क्षेत्र उसमें शामिल किए जाएंगें और उसमें आपका क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो एशियन डवैल्पमैंट बैंक के माध्यम से 4751.24 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, इसमें जिला सिरमौर के दो विधान सभा क्षेत्र

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.8.2018/1130/av-ag/1

प्रश्न संख्या : 138 ---------- क्रमागत

श्री सुख राम------- जारी

जो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें रेणुका और शिलाई दो ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर गर्मियों में पीने-के-पानी की ज्यादा कमी हो जाती है। क्या द्वितीय चरण में इन दो विधान सभा क्षेत्रों के अधिकतर क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जायेगा?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर सोमवार को स्टेटमैंट देंगे।

24.8.2018/1130/av-ag/2

अध्यक्ष : आज के प्रश्न, श्री नरेन्द्र बरागटा जी अपना प्रश्न करेंगे।

<u>प्रश्न संख्या 591</u>

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इनको बधाई भी देना चाहता हूं कि युवा आगे बढ़े और देश व इस प्रदेश का नाम दुनिया में ऊंचा करें। उसके लिए सुविधा जुटाने हेतु हमारे नौजवान मंत्री तथा मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से ऐफट्र्स शुरू किए जा रहे हैं; इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। साथ में, मैं मुख्य मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आभारी हूं। आप हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर थे और वहां पर ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्तर का जो 8 लेन का सिन्थेटिक ट्रैक बनने वाला है; आपने उसका शिलान्यास किया है। उस ट्रैक के निर्माण के लिए आपने एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके टैंडर्ज और दूसरी फोर्मेलिटीज कब तक पूरी हो जायेगी? मेरा निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी-से-जल्दी पूरा करने की कोशिश करें ताकि हमारे नौजवान खिलाड़ियों को शीघ्रातिशीघ्र सुविधाएं मिल सकें। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल का खिलाड़ी अपने स्तर पर बहुत कोशिश करता है ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़रा उतर सके। मैं युवा वर्ग को बधाई देना चाहता हूं, खासकर हमारी बेटियां इस क्षेत्र

में उभरकर आगे आ रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा संस्थान खोलने का विचार रखते हैं या कोई ऐसी योजना है जैसे कोई एक बड़ी एकेडमी जहां पर एक छत के नीचे प्रदेश के खिलाड़ियों को सुविधा प्राप्त हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या आप किसी ऐसी योजना पर भी विचार कर रहे हैं जो केवलमात्र हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें?

24.8.2018/1130/av-ag/3

अध्यक्ष : माननीय वन मंत्री जी अपना उत्तर दें उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आज तीन बेटियों ने कबड्डी में और देश को आगे ले जाने में जो कमाल किया है उसके लिए आप उनको बधाई जरूर दें।

वन मंत्री (युवा सेवाएं एवं खेल): पहले तो आज जिन तीन बेटियों ने नाम कमाया है उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हमने 13 गतिविधियां चिन्हित की हैं लेकिन मैं अभी हर गतिविधि पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। जुब्बल-कोटखाई में सिन्थेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए 90 बीघा भूमि उपलब्ध है। मैं इस बारे में एक और जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बरागटा जी वर्ष 2002 में जब बागवानी मंत्री थे तो इसका फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा ही रखा गया गया था। इसके निर्माण में कुल 12.54 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे और इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

श्री टी सी द्वारा जारी

24.08.2018/1135/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 591 क्रमागत्
माननीय वन मंत्री..... जारी

इसके लिए एक करोड़ रुपया दे दिया गया है और इसको दो वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए भारत सरकार से सात करोड़ रुपये की और मांग की गई है और इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार इस सिंथैटिक ट्रेक को दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद जब कोई जीत कर आते हैं तो वह कई प्रकार के इनामों की घोषणा करते हैं। पहले ओलंपिक में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपया, द्वितीय स्थान पाने वाले के लिए 75 लाख रुपये और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 50 लाख रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मैडल लेकर आता है तो हम उसको दो करोड़ रुपये देंगे यानि इस राशि को दोगुना किया है। जो खिलाड़ी सिल्वर मैडल लेकर आएंगे ,उनको एक करोड़ रुपये और जिनको पिछली सरकार 25 लाख रुपये देती थी, उनको हम 50 लाख रुपये की राशि देंगे। इसके अलावा कॉमनवैल्थ गेम्ज और एशियन गेम्ज के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि गोल्ड मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मु0 20 लाख रूपये दिए जाएंगे जोकि पिछली सरकार के समय में केवलमात्र मु0 10 लाख रुपये थे। सिल्वर मैडल पाने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपये और ब्रॉन्ज़ मैडल पाने वाले खिलाड़ी को मु0 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पूरा साल भर खेल के क्षेत्र में कौन-कौन सी गतिविधियां चलनी चाहिए इसके लिए खेल विभाग ने एक कलैंडर बनाया है कि हम जनवरी से दिसम्बर महीने तक किस महीने में किस दिन कौन-कौन से खेलों को करवाएंगे। इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो सिंथैटिक ट्रैक है उसको दो वर्षो में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।

24.08.2018/1135/TCV/AG/2

श्री सुरेश कश्यपः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आजकल खेलों का सीज़न चल रहा है और स्कूलों में आजकल अंडर 14 व अंडर 19 टूर्नामैंट्स हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आजकल स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है लेकिन बच्चों को लाने और ले जाने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। छात्र-छात्राओं को छोटी-छोटी गाड़ियों में भरकर ले जाया जाता है और उससे लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में धन की उचित व्यवस्था की जाये क्योंकि स्कूलों के पास पर्याप्त धन नहीं होता है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

24-08-2018/1140/NS/DC/1

प्रश्न संख्याः 591 ------क्रमागत

वन मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट और शिक्षा विभाग मिल करके काम करेंगे। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि दोनों विभाग मिल करके कोई निष्कर्ष निकालेंगे ताकि धन की कमी के कारण खेलों का आयोजन न रूक पायें। शिक्षा विभाग और खेल विभाग आपस में तालमेल बैठा करके इसको ठीक करेंगे और इसकी ठीक व्यवस्था करेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्गः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्कूलों की जो खेलकूद प्रतियोगितायें चल रही हैं, उसमें जो हमारे खिलाड़ी छात्र/छात्रायें हैं; उनको सुविधायें

प्रदान करने के लिए और विशेषकर इनके लिए जो डाईट की व्यवस्था होती है, उसमें क्या कोई बढ़ोतरी की गई है या नहीं?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि शिक्षा विभाग और खेल विभाग मिल करके इस पर कोई निर्णय करेंगे। निश्चित रूप से डाईट के मामले और खेलों की तैयारी के लिए जो भी राशि बढ़ानी है, इसको दोनों विभाग मिल करके निर्णय लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो खेल कलैंडर दिया है, वह अगस्त महीने का है। मुझे भी अपने विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन जगह खेलों के उद्घाटन और समापन पर जाने का मौका मिला। लेकिन बरसात इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर खेलों का आयोजन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस शैड्यूल को चेंज करने की आवश्यकता है। मेरे अनुसार इन खेलों का आयोजन अगस्त महीने के बजाए सितम्बर या अक्तूबर में होना चाहिए। जिन भी खेलों का आयोजन आजकल हो रहा है, वे बारिश की वज़ह से नहीं हो पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अगस्त महीने में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस कलैंडर को चेंज करने की आवश्यकता है।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो अभी तक खेलों का आयोजन पिछले कलैंडर के मुताबिक हो रहा है। जो खेलों का कलैंडर हमने बनाया है उसे हम माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा करके इसी विधान सभा सत्र के बीच में लायेंगे। यह कलैंडर हमने तैयार कर दिया है और उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। जो सुझाव आपने दिये हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है।

24-08-2018/1140/NS/DC/2

श्री राकेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय राजिन्द्र गर्ग जी का था कि जो स्कूलों के टूर्नामैंट होते हैं, वहां पर बच्चों के भोजन और बाकी व्यवस्थाओं के लिए 40 या 50 रुपये की डेली दी जाती है और इसमें सारी व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में इस पर विचार करें और डाईट बढ़ाई जाये।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है, हम इसका स्वागत करते हैं।

<u>शिक्षा विभाग और खेल विभाग इसको मिल करके बढ़ायेंगे।</u>

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बोल ही दिया है कि हम इसको मिल करके बढ़ायेंगे और यह बात आश्वासन के रूप में आ गई है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने इन सारी शंकाओं का समाधान किया है। एक-दो विषयों के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। हमारा एक विषय खेल कलैंडर का आता है और जब extreme rain season होता है तो हर वर्ष खेलों का आयोजन इसके बीच में होता है। मुझे लगता है कि इस विषय को ले करके शिक्षा विभाग और खेल विभाग को मिल करके हल निकालना चाहिए क्योंकि अकैडमिक कलैंडर में भी ये कलैश नहीं होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। लेकिन इन खेलों का आयोजन बरसात के मौसम से आगे या पीछे कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। यहां पर दोनों विभागों के मंत्री बैठे हुए हैं और वे आपस में को-ऑर्डिनेशन के माध्यम से कोई रास्ता निकालें।

दूसरा विषय यहां पर भोजन (डाईट) का आया है और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कह भी दिया है कि हम इसको बढ़ायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह सचमुच में एक विषय है, जिस पर सोचने की आवश्यकता है क्योंकि डाईट बहुत कम है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के टूर्नामैंट का आयोजन कहीं पर किया जाता है तो स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाता है। यहां तक कि वहां के जो स्टॉफ वाले हैं, उस कल्स्टर/स्कूल के जो टीचर्ज़ हैं वे मिल करके बहुत सारी व्यवस्थायें करते हैं। वे अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा इक्ट्ठा करते हैं और स्थानीय लोगों का सहयोग ले करके बाज़ार से राशन इक्ट्ठा करते हैं तथा फिर टूर्नामैंट का आयोजन

किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उस इलाके में टूर्नामैंट का आयोजन करना एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है क्योंकि कई जगहों पर इस प्रकार का सहयोग करने वाले लोग होते हैं और कई जगहों पर सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके बारे में मुझे लगता है कि हमें विचार करने की आवश्यकता है और हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। एक तो डाईट के पैसे को बढ़ायेंगे और वहां पर

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

24.08.2018/1145/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 591... जारी

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि इस कार्यक्रम के तहत चलाऊ काम किया जाए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था बच्चों के लिए उचित नहीं है।

तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन का विषय एक गंभीर विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में टूर्नामैंट ओर्गेनाइज किए जाते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की काफी दिक्कत आती है। शहरी क्षेत्रों में ऐसी दिक्कतें कम आती हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म नहीं है। कई जगह तो अध्यापक गाड़ियां हायर करके बच्चों को टूर्नामैंट में ले जाते हैं। यदि उस गाड़ी में 10 बच्चों को बैठाने की क्षमता हो तो उसमें 15 बच्चों को बैठा दिया जाता है। एक्सिडैंट्स का सबसे बड़ा कारण ऑवर लोडिंग होता है और इस दृष्टि से हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। इसमें क्या मैकेनिज्म डिवैल्प किए जा सकते हैं; जितनी बच्चों की स्ट्रैंथ हो उसके मुताबिक हम HRTC या दूसरी व्यवस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रावधान करें; उस बात पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।। जब टूर्नामैंट समाप्त होता है और बच्चे जीत कर आते हैं तो वे बस की छत पर चढ़कर 'शिल्ड' को दिखाते हुए नारे लगाते हैं। वे सभी बच्चे जोश में होते हैं। जोश में होना अच्छी बात है लेकिन ऑवर लोडिंग के कारण एक्सिडैंट की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ा आर्थिक बोझ जरूर पड़ेगा लेकिन इस पर सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्षः माननीय वन मंत्री जी आप माजरा के Astroturf का भी ध्यान रखना।

24.08.2018/1145/RKS/DC-1

<u>प्रश्न संख्याः 592</u>

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के 7 महीनों के कार्यकाल में नाचन विधान सभा क्षेत्र की 4 स्कीमों के लिए 6,14,16000/-रुपये की राशि माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से स्वीकृत हुई है, जिसके लिए मैं निर्वाचन क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। पूर्व सरकार के कार्यकाल में हम नाबार्ड से संबंधित एक नहीं अनकों प्रश्न विधान सभा में लगाते रहे परंतु उस समय नाबार्ड के तहत एक भी योजना नाचन विधान सभा क्षेत्र को नहीं मिली। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने 7 महीनों के कार्यकाल में नाबार्ड के तहत 6,14,16000/-रुपये की राशि नाचन विधान सभा क्षेत्र को प्रदान की है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नाचन विधान सभा क्षेत्र की कुछ और भी योजनाएं नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। जिनमें खंडैल ब्रिज और संजाला-कमरूनाग सड़क का निर्माण कार्य नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। 'इम्प्रूवमैंट ऑफ जॉन नम्बर- 4 टू जॉन नम्बर-8' जिसकी आपने विधिवत् रूप से घोषणा भी की है। इसके साथ ही भलोठी -सरयाच, राखगलू -जनयाणी और जहल- बूखरात योजनाएं भी नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन योजनाओं को भी शीघ्रातिशीघ्र नार्बाड से स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

श्री बी0एस0 द्वारा.... जारी

24.08.2018/1150/बी.एस/एच.के/-1

प्रश्न संख्याः 592 क्रमागत

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र से श्री विनोद कुमार जी, जब से इस विधान सभा में चुनकर आए हैं तब से लेकर अब तक इन्होंने विधायक

प्राथमिकता के तहत कुल 42 स्कीमें भेजी हैं। इनमें से 2 स्कीमें नाबार्ड के माध्यम से और 2 स्कीमें विधायक प्राथमिकता एवं अन्य मदों से स्वीकृत हुई हैं। अब तक कुल 4 योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है। इसके साथ ही मैं यह भी देख रहा था कि इसके अलावा 34 स्कीमों की डी.पी.आर. बनना बाकी है। माननीय सदस्य का यह कहना कि कुछ स्कीमों की डी.पी.आर. बन करके नाबार्ड के लिए स्वीकृति हेतु चली गई हैं। इस बारे में मेरी जानकारी के अनुसार तीन स्कीमें गई हैं और एक स्कीम नाबार्ड द्वारा अस्वीकृत की गई है। जितनी भी योजनाएं नाबार्ड के लिए गई हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी ये स्कीमें स्वीकृत हों। जब भी हम नाबार्ड के लिए स्कीमें भेजते हैं, उसमें भी पैसे को लेकर एक सीमा रहती है। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्र जिनके लिए पिछले समय में नाबार्ड के तहत बहुत कम स्कीमें स्वीकृत हो पाई हैं, उन क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के बराबर नाबार्ड के तहत पैसा मिले । माननीय सदस्य ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में एक भी स्कीम उनके चुनाव क्षेत्र में स्वीकृत नहीं हुई है। ऐसे में उन चुनाव क्षेत्रों को संतुलित करने का सरकार का प्रयास रहेगा। नाबार्ड के तहत समग्र विकास हो ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।

अध्यक्षः वैसे यह प्रश्न नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र से संबन्धित था, परंतु माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के उपरांत माननीय सदस्य श्री रविन्द्र कुमार जी को अनुमति दी जाती है।

श्री रविन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जो 90 करोड़ रुपये की किटी दी जाती है यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 90 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, तो क्या सरकार उस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है; क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन देगें?

24.08.2018/1150/बी.एस/एच.के/-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाए तो बहुत सारे विधान सभा चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले काफी लम्बे अरसे से नाबार्ड की स्कीमें बहुत कम स्वीकृत हुई हैं और कुछ चुनाव क्षेत्रों में तो पिछले पांच वर्षों में स्कीमें स्वीकृत हुई ही नहीं हैं। इसलिए संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि जहां पर कोई विकास कार्य हुए ही नहीं हैं वहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे विकास कार्य हो चुके हैं और वहां पानी और सड़कों की उतनी मांग नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है, उस संबन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले सिलिंग 80 करोंड़ रुपये तक थी, अब हमनें इस बजट में इसे बढ़ा कर 90 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें हमने 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। मुझे लगता है कि फिलहाल यह रकम काफी अच्छी है। इन सारी बातों पर अगले बजट में विचार करेंगे।

24.08.2018/1150/बी.एस/एच.के/-3

प्रश्न संख्याः 593

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र नेरवा में परिवहन निगम का डिपू खुला है और वहां पर दो बीघा भूमि उपलब्ध है।

श्री डी.टी.द्वारा जारी.....

24.3.2018/1155/DT/AG -1

प्रश्न संख्याः 593...क्रमागत

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

कुछ भूमि पुलिस विभाग के नाम थी परंतु पुलिस विभाग ने थाना कहीं ओर बना लिया है। पुलिस विभाग ने जो पहले पैसे जमा करवाए थे वे पैसे परिवहन विभाग ने पुलिस विभाग में जमा करवा दिए हैं लेकिन पुलिस विभाग ने अभी तक उसका एन0 ओ0सी0 नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अभी हाल ही में मेरे चुनाव क्षेत्र नेरवा गए थे। नेरवा डिपो के अधीन जितनी भी बसें है उनमें शिमला डिपो का नाम लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आश्वासन चाहता हूँ कि बसों में नेरवा डिपो का नाम जल्दी-से-जल्दी लिखा जाए । नेरवा डिपो को बनाने के लिए 2 बीघा भूमि उपलब्ध है और 4 बीघा भूमि में FCA क्लीयरैंस मिल गई है। इसके लिए पुलिस विभाग के पास पैसे भी जमा करवा दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपो बनाने के लिए पैसे का प्रावधान कब तक कर दिया जाएगा और इसकी टैंडर प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने ठीक कहा की नेरवा डिपो के पास वर्तमान में 2 बीघा जमीन उपलब्ध है। लेकिन नेरवा डिपो और बस अड्डा बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खसरा नं0 302 में पुलिस विभाग के नाम 2,36,125/-रूपये भी जमा करवा दिये हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा की पुलिस वाले जल्दी से उसका ए0नो0सी0 दे दें। इस कारण से यह काम रूका पड़ा है। दुसरा नेरवा में वर्कशॉप के लिए 4.5 बीघा भूमि का चयन किया गया है। मैं बस अड्डा मनैजेमेंट अथॉरिटी की ओर से यह कहना चाहूँगा की बहुत जल्द FCA क्लीयरैंस करवाकर भूमि बस अड्डा मनैजेमैंट अथॉरिटी के नाम करगें और इसे बनाने के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। माननीय सदस्य ने जो डिपो नाम परिवर्तन की बात की है, उसे हम करवा देंगे।

24.3.2018/1155/DT/AG -2

प्रश्न संख्याः 594

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)ः अध्यक्ष जी मैं माननीय मंन्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रश्न का कंपलीट उत्तर दिया है। लेकिन जोन सी0 में अभी तक काम नहीं हो पाया है। उसमें तकरीबन 2.5 किलोमीटर लाइन अभी 'ले' करनी है। एस.टी.पी. में 1.67 एम0एल0डी0 का जो पिछले 5सालों से डिफालट पड़ा था उसे आपने चालू करवा दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यावद। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस स्कीम को पूर्ण करवाने की कृपा करें क्योकि इसके लिए 4.55 करोड़ रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है। यह स्कीम वर्ष 1995 में शुरू हुई है। इसमें थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े-बड़े गांव हैं क्या वहां पर भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने हेतु सरकार विचार करेगी ?

श्री एन जी द्वारा जारी ..

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्रीः अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर धन की कोई कमी नहीं है इस स्कीम को पूरा करने के लिए, जमीन का थोडा सा डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट को एस.डी.एम. सरकाघाट लगातार हियरिंग कर रहा है। जैसे ही जमीन का डिस्प्यूट सोलव होगा, तब तुरन्त इसे पूरा कर दिया जाऐगा और साथ में जो माननीय सदस्य जी की चिन्ता है, कि पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसे बहुत सारे गांव है जिन गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है और ऐसी बहुत पंचायतें हैं जो दूसरी पंचायतों के साथ घनी आबादी के कारण आपस में बिलकुल जुड चुकी हैं। क्योंकि सिवरेज की जो व्यवस्था है वो केवल मात्र अभी तक शहरी क्षेत्रों में ही है। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहॉ पर सिवरेज की व्यवस्था कर दी जाए।

प्रश्न काल समाप्त

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-2

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सदन में वापिस आए।)

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सदन को **साप्ताहिक** शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्यमन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो इस प्रकार है -ः

शुक्रवार, 24 अगस्त, **2018** 1. शासकीय/विधायी कार्य ।

<u>स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमती से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल रखता हूँ, जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :-

1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 3);

(2) हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 4);

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-3

(3) हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का अधिनियम संख्यांक 5);

(4) सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 6);

(5) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 7); और

(6) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 8) ।

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-4

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्यमन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, तकनीकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए (3)-19/99 दिनांक 12.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.07.2018 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, कला सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए3(55)99 दिनांक 28.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.05.2018 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-53/99 दिनांक 18.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2018 को प्रकाशित; और

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः3-1/75-फिन(टी0एण्ड0ए0)-IV दिनांक 19.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2018 को प्रकाशित ।

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-5

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँः-

i. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I (राजपत्रित) और संविधा भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ए-ख(2)62/2016 दिनांक 27.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2018 को प्रकाशित;

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-6

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0-सी0-ए(3)-1/2016 दिनांक 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.09.2017 को प्रकाशित; और

iii. अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 26(2) के अन्तर्गत अभिलाषी विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम, 2017 ।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-7

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः- अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँः-

i. समिति के **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है;
ii. समिति के 10**वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा

कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

iii. समिति के **पंचम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 47वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-8

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उप-स्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बलबीर सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँः-

i. समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति के **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **लोक निर्माण विभाग** द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

24/8/2018/1200/वाई0के0/एन0जी0-9

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उप-स्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति के **5वें मूल प्रतिवेदन** जोकि **उद्योग विभाग** की गतिविधियों से सम्बन्धित संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नरेन्द्र बरागटा श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

24/08/2018/1205/RG/YK/1
श्री बिक्रम सिंह जरयाल के पश्चात

अध्यक्ष : अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, नियम समिति, नियम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति (वर्ष 2018-19) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

24/08/2018/1205/RG/YK/2

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष : गत् दिन हुई दुर्घटना के संबंध में माननीय वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी वक्तव्य देंगे।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को दो दुर्घटनाएं हुई हैं। अभियोग संख्या : 224/18, दिनांक 23-08-2018 ज़ेर धारा 279, 304 (ए), भारतीय दण्ड संहिता की वस्तुस्थिति रिपोर्ट बारे - राजकीय कार्य के संबंध में निवेदन है कि है कि दिनांक 23-08-2018 को मा. मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह, नं. 443, थर्ड आई.आर.बी.एन, पण्डोह के बयान पर उपरोक्त मुक़दमा थाना में दर्ज़ हुआ। जो कल दिनांक 23-08-2018 को मा. मुख्य आरक्षी, ठाकुर सिंह, नं. 443, उपरोक्त ने थाना में बजरीया दूरभाष सूचना दी थी कि एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर राहणी नाला के पास से ढांक से नीचे गिर गई है। जो इस सूचना पर मन प्रभारी थाना मनाली उप-निरीक्षक, निर्मल सिंह मय सहयोगी कर्मचारियों सहित घटनास्थल मुक़ाम राहणी नाला पहुंचा तो पाया गया कि एक गाड़ी नं. एच पी-45 7000, स्कार्पियो दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरी थी जिसमें सवार सभी 11 व्यक्ति, महिलाएं एवं बच्चों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी। जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं :- 1. श्रीमती अंजना, पत्नी श्री मुकेश कुमार, निवासी, गांव विष्ठो, डाकघर लुज, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 30 साल, 2. नक्श, पुत्र श्री मुकेश कुमार, निवासी गांव विष्ठो, डा. लुज, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 15 साल, 3. प्रेम राज, पुत्र मान सिंह, निवासी गांव गोश्ती, डाकघर करयास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 29 साल, 4. धर्म सिंह, पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी गांव चलौली, डाकघर धरभास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 40 साल, 5. कल्पना, पत्नी राकेश, निवासी गांव सौर व डा.पुर्वी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 40 साल, 6. आयुष्मान, निवासी गांव सौर व डा. पुर्वी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र केवल मात्र दो साल, 7. कुंती उर्फ भोली, पुत्री धर्म सिंह, निवासी गांव चलौली, डाकखाना धरभास, तहसील पांगी, जिला चम्बा, 8. मोनिका, पुत्री बेसूराम, निवासी ग्राम कुफा, डाकघर किलाड़, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 23 साल, 9. मीना, पत्नी राजेश, निवासी ग्राम किर्तिंग, डाकघर सासा, तहसील व जिला लाहौल-स्पिति, 10. प्रेम सिंह, पुत्र

देव राम, निवासी गांव चासंग भटौरी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, उम्र 22 साल और 11. ऊषा कुमारी, पुत्री श्री मेहर चन्द, निवासी गांव खजियार, जिला चम्बा, उम्र 17 साल।

24/08/2018/1205/RG/YK/3

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदया जनाब एस.डी.पी.ओ. मनाली व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। खाई से पुलिस व स्थानीय मजदूरों की सहायता से मृतकों की लाशों को सड़क पर लाया गया। मौके पर ही डाक्टर्ज की टीम द्वारा सभी लाशों का पोस्टमॉर्टम मृतकों के रिश्तेदारों की उपस्थिति में किया गया व बाद में पोस्टमॉर्टम मृतकों की लाशों को ब्राये अन्तिम संस्कार मय उनके सामान की शिनाख्त करने के बाद उनके रिश्तेदारों के सुपुर्द किया गया।

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2018/1210/MS/AG/1

वन मंत्री जारी------

यह हादसा उपरोक्त गाड़ी के चालक प्रेम राज, पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम गोष्टी, डाकखाना करियास, तहसील पांगी, जिला चम्बा का गाड़ी की तेज रफ्तारी व लापरवाही से चलने के कारण घटित हुआ है। अभियोग की आगामी तफ्तीश उप-निरीक्षक निर्मल सिंह, अन्वेषणाधिकारी, पुलिस थाना मनाली के द्वारा की जा रही है।

अध्यक्ष जी, एक दूसरी दुःखद दुर्घटना शिमला जिला के ननखड़ी में हुई है। इसमें नीरज, सुपुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम/डाकघर दनावली, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला ने पुलिस को बयान दिया है कि वह दिनांक 23 अगस्त, 2018 की रात को उसके गांव के अन्य पांच लोगों के साथ सुरेश कुमार की गाड़ी नम्बर एच0पी0-03डी-0499बी/कैम्पर में बैठकर घर जा रहा था। जब गाड़ी खलूट (धौणा) स्थान पर पहुंची तो तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी 150

से 200 मीटर नीचे घासनी में जा गिरी। गाड़ी के गिरने के कारण नीरज, चालक सुरेश कुमार, सुन्दर व हेमराज को चोटें आईं व आशीष, सुरेन्द्र व दलीप कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में अभियोग संख्या 44/18, दिनांक 24 अगस्त, 2018, जेर धारा 279, 337, 304(ए) आई0पी0सी0 पुलिस थाना ननखड़ी, जिला शिमला में पंजीकृत किया गया है जिसका अन्वेषण जारी है। अध्यक्ष महोदय, यही सूचना मुझे रखनी थी। धन्यवाद।

24/08/2018/1210/MS/AG/2

<u>नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र बरागटा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अति गम्भीर विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, आजकल सेब सीज़न पूरे यौवन पर है और बरसात के कारण कुछ सड़कों का काफी नुकसान हुआ है जिस वजह से ठियोग-हाटकोटी सड़क के ईर्द-गिर्द बसने वाले बागवान/किसान और आमजन के बहुत सारे परिवार सकते में है। विभिन्न स्थानों पर उनके घरों और बागीचों के रास्ते लगभग समाप्त हो गए हैं। इस सड़क के मलबे के कारण उस क्षेत्र में गम्भीर समस्या खड़ी हो गई है और क्षेत्र की पेयजल योजनाएं टूट रही हैं। गांवों को जो पगडण्डियां जाती हैं, जिनमें सुबह से शाम तक सबने चलना होता है, जोकि एक-दूसरे गांवों को मेन सड़कों से जोड़ती हैं, वे लगभग समाप्त हो गई हैं। बागवानों के बागीचों के बहुत सारे एरिया में उस सड़क का सारा मलबा घुस गया है। सैंकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है और मुझे यह बोलते हुए कष्ट हो रहा है कि जो इस सड़क में ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको पिछली सरकार में संरक्षण प्राप्त होता रहा। उन्होंने अन-साइंटिफिक हैपजार्ड तरीके से कटिंग करके जिस तरह से सैंकड़ों परिवारों को खतरे में डाल दिया है, मैं उसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। मलबे को डम्पिंग साइट में

न डाल करके नालों में फैंका गया जोकि आज उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आ गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मैं डिटेल में कुछ तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं और मुझे पूरी आशा है कि उसमें आप हस्तक्षेप करेंगे तथा उस क्षेत्र को राहत पहुंचे, ऐसे आप कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष जी, इस टैण्डर को वर्ष 2007 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिना वन विभाग की अनुमति से लगा दिया। बिना लैण्ड को एक्वायर करके लगा दिया यानी लैण्ड ही एक्वायर नहीं की

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

24.08.2018/1215/जेके/एजी/1

श्री नरेन्द्र बरागटाः-------जारी---------

और टैंडर फ्लोट हो गए। चाइनीज़ कम्पनी को ठेका मिल गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमने सारी लैंड एक्वायर करवाई, फोरैस्ट से क्लीयरैंस करवाई और चाइनीज़ कम्पनी के जो ठेकदार थे, तब तक उनकी लेबर वापिस चली गई, उनके अधिकारी यहां से वापिस चले गए। उसका परिणाम यह हुआ कि सड़क अवरुद्ध हो गई। दिल्ली में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, वहां उनको वीज़ा न मिलने का मुद्दा उठाया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद प्रधान मंत्री जी से बात की। माननीय वीरभद्र सिंह जी, जो केन्द्र में उस समय के पावर मिनिस्टर थे, उनके पास मैं खुद निवेदन करने के लिए गया लेकिन वीजा न मिलने के कारण यह सड़क रुक गई। उसके बाद हिमाचल में हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस सरकार वापिस आ गई। फिर एक ठेकेदार को ढूंढा गया। वह सी एण्ड सी कम्पनी का कोई ठेकेदार था। मुझे

नहीं पता उसको कहां से लाया गया। रिकॉर्ड इस बात के साक्षी हैं कि वह ठेकेदार, जब टेंडर फ्लोट किए, फाईनैंशियल बिड में वह फेल था, टैक्निकल बिड में भी फेल था उसके बावजूद भी उसको टेंडर दे दिया गया। इसके दो पैकेजिज़ बनाए गए थे ताकि काम शीघ्र हो। क्वालिटी के साथ कोई समझौता न हो, लेकिन इसी को काम दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके दो पैकेज़ बनाए गए थे ताकि काम शीघ्र हो, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ न हो। एक ठियोग से खड़ा पत्थर और दूसरा खड़ा पत्थर से रोहड़ू। दोनों के दोनों काम एक ही कम्पनी को दे दिए गए। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत

24.08.2018/1215/जेके/एजी/2

जबरदस्त भ्रष्टाचार की बू आ रही है जिसको अभी आगे मैं प्रूव करना चाहता हूं। हैरानी की बात यह है कि इस फर्म ने सारों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। सारे अधिकारी भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार रहते थे। आप हैरान होंगे कि एडवांस में डीजल की सप्लाई, सीमेंट की सप्लाई और पैसों की सप्लाई, उसको बिना कुछ काम किए दिया जाता था। सरकार इतनी मेहरबान क्यों रही, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने इस सन्दर्भ में 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक पद यात्रा की और साथ में मैंने एक रिट माननीय हाई कोर्ट में डाली। उसका संज्ञान लेते हुए उसमें एक कमेटी बनी। मैंने, माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करना है मेरे ख्याल में यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा और यह आप भी मानते हैं कि यह गिनिज बुक रिकॉर्ड में भी आ सकता है। यह इसलिए आ सकता है कि अभी तक

माननीय हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से कम से कम 100 हीयरिंग हो चुकी है, जिसके कारण यह सड़क बनी। जो उस क्षेत्र के राजनीतिक लोग हैं, खास करके कांग्रेस के मेरे मित्र उसका श्रेय लेना चाहते हैं लेकिन हमें उसकी कोई चिन्ता नहीं है। आप श्रेय लीजिए। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डालना चाहता हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वर्ल्ड बैंक ने इनको एक्सटैंशन देने से मना कर दिया। तीन बार इन्होंने एक्सटैंशन मांगी इनको इन्कार कर दिया। अंत में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपका अत्यन्त धन्यवादी हूं कि इनकी

24.08.2018/1215/जेके/एजी/3

एक्सटैंशन खत्म कर दी और वर्ल्ड बैंक ने विद्ड्रॉ कर दिया। और काम खड़ा होने की कगार पर आ गया। इस बीच हमारी सरकार आ गई। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मुख्य मंत्री बनें। मुझे आपको इसलिए भी बधाई देनी है शायद कैबिनेट की दूसरी या तीसरी मीटिंग में आपने सड़क को चालू रखने के लिए अलग से 60 करोड़ रूपए का प्रोविज़न किया ताकि सड़क बन्द न हो, आगे बढ़े, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जंगलों में जो पेड़ खड़े थे, बड़े-बड़े बोर्ड व बड़े-बड़े पत्थर ऊपर से फेंके गए और वे छलनी हो गए। वहां पर पर्यावरण की जो चीर-फाड़ हुई वह आज भी आप देख सकते हैं। मैं यहां पर प्रूफ लाया हूं और मैं उसको यहां सभा पटल पर भी रखना चाहूंगा। लोगों की सैंकड़ों सड़कें, उनके घर खतरे में प़ड़ गए हैं। पेयजल योजनाएं ठप्प हो गई

हैं, गांवों के रास्ते बन्द हो गए, पानी के नैचुरल सोर्सिज़ डिस्ट्रॉय हो गए और इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। शेर सिंह ठाकुर, लायक राम ठाकुर, राजेन्द्र ठाकुर, संजय ठाकुर, कृष्णा देवी, पदम दास, मोहन शर्मा ये चलैर के और बागा क्षेत्र के हैं। इन लोगों के हरे-भरे सेब के पेड़ 15-20 बीघे में थे जो कि तबाह हो गए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

24.08.2018/1220/SS-DC/1

श्री नरेन्द्र बरागटा क्रमागतः

सारा मलबा बगीचों में चला गया। 15 से 20 फुट मलबा पेड़ों को किनारे करके आगे निकल गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रभावित गांव/क्षेत्र हैं उसमें कोटखाई बस-स्टैंड खतरे में है। कोटखाई का बाजार एन0ए0सी0 खतरे में है। डम्पिंग कहीं और होनी थी लेकिन डम्पिंग साइट न होने के कारण सारा मलबा माननीय मुख्य मंत्री जी वहां डाल दिया गया। यह खतरे की घंटी है अगर मलबा बाजार में चला गया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इस तरफ उस वक्त की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। दरकोटी पंचायत के कराली गांव में श्री सुरेश, जतिन, रमेश और संजीव जी के घर भी खतरे में पड़ गए हैं। गिरी खड्ड में जो मलबा इसी कम्पनी द्वारा डाला गया उससे कोटखाई बस-स्टैंड के साथ-साथ कोटखाई बाजार संकट में हैं। जलटाहर के श्री मोहन चौहान, श्री राम लाल, यशबीर जस्टा (डमैहर) प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बड़वी और सलयाणा का पूरा गांव प्रभावित हुआ है। दरकोटी, गरावग, प्रेम नगर, कोकूनाला और डागवीं की पूरी पंचायतें प्रभावित हुई हैं। आज ये लोग डर-डर कर अपने घरों में जा रहे हैं। गुम्मा पंचायत, पांदली पंचायत, पुड़ग पंचायत और हाटली, बैकानेवल, बाग डोमहैर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जो छोटी-छोटी सड़कें थीं, जब मलबा मेन रोड को क्रॉस करके आगे चला गया तो वे भी बंद हो गईं। मेजर रोड और लिंक रोड सारी मलबे में चली गईं। खड़ापत्थर से ले करके लगभग हाटकोटी तक

बड़ी-बड़ी दीवारें नीचे चली गईं। मैंने इस संदर्भ में एक प्रश्न भी लगाया है अगर वह लगेगा तो मैं उस वक्त उसमें चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हुआ है। पूर्व सरकार द्वारा तीन-चार महीने में जो करोड़ों रुपयों की दीवारें लगाई गई थीं, वे नीचे चली गईं। मैंने प्रश्न में यही पूछा है कि पिछले तीन साल के अंदर कितनी दीवारें इनकी टूटी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर इनका सर्वेक्षण करवायेंगे तो पता चलेगा कि करोड़ों की दीवारें सारी-की-सारी नीचे चली गई हैं। यानी कि पूरा-का-पूरा क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज हुआ है जोकि बहुत ही शर्मनाक बात है।

जहां तक जंगलों की बात है, मैं बड़ा हैरान हूं, आजकल जो पर्यावरण के बड़े-बड़े विद्वान और पत्रकार हैं वे ज़रा जाकर देखें कि सैंकड़ों पेड़ों को छलनी कर दिया गया है। सैकड़ों पेड़ खतरे में हैं और किसी को गिरा दिया गया है। वे

24.08.2018/1220/SS-DC/2

कम-से-कम 20-25 फुट मिट्टी में दब गए हैं। जैसे उनकी सांस रोकने के लिए उनके इर्द-गिर्द बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ सड़क बनानी थी। चूंकि चुनाव नज़दीक थे, सड़क बना दो ताकि उसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके चाहे पर्यावरण की छज्जियां उड़ जाएं, चाहे लोगों के मकान खतरे में पड़ जाएं, चाहे वहां पर कोई भी कष्ट लोगों को मिले, इस तरह का नज़ारा वहां देखने को मिला है। कोटखाई बाजार की पेयजल योजना ठप, बागा चलनायर की पेयजल योजना भी खत्म हो गई। सलायणा, गाजटा, मंदरोली, सैन्ताड़ी और दरकोटी पंचायत की सारी पेयजल योजनाएं इसके कारण ठप हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथ कुछ तस्वीरें लाया हूं, मैं इनको विधान सभा के पटल पर भी रखना चाहूंगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस बेरहमी के साथ मलबा डम्पिंग साइट पर न डाल करके हर कहीं डाल दिया गया है। आज अगर मैं आपको यह फोटो दिखाऊं तो इसमें कम-से-कम 50 पेड़ दयार और चीड़ के रूंड-मुंड करके फेंक दिए गए है। बड़े-बड़े बोल्डर यहां पड़े हैं। यह देखिये, बगीचे में हमारा बागवान, जिसने बच्चे की तरह सेब के पौधे पाले थे, वह सेब के पौधों के बीच में खड़ा होकर विलाप कर रहा है। यह हालत इस कम्पनी ने बना दी है और पूर्व सरकार देखती रह गई। इतना संवेदनशील मुद्दा है, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

यह हैरानी की बात है। जब ये अखबारों में खबरें लगीं तो उसमें एक अधिकारी कहते हैं कि मलबा हटा दिया जायेगा। यानी कि आप जख्म पर नमक छिड़कना चाहते हैं। आपका अपने ठेकेदार पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या हो गया है! मैं वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि वैसे तो वहां के विधायक को साथ ले जाते नहीं थे लेकिन वीरभद्र सिंह जी क्योंकि प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, इनको वहां की पीड़ा थी, वे एक बार खड़ापत्थर में गए। सारे अधिकारी बुलाए। ठेकेदार को भी डांटा और कहा कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं ये काम ठीक नहीं हो रहा है। इसकी गुणवत्ता को आप मैंटेन करिये। लेकिन उसके बावजूद भी वैसे ही काम चलता रहा और किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2018/1225/केएस/डीसी/1

श्री नरेन्द्र बरागटा जारी----

एक जांच दल बने, वह आज ही उस क्षेत्र में जाएं और मॉड्यूल मैज़रमैंट इसमें करें बाकी मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं। आप इसमें इन्क्वायरी करवाएं, मुझे खुशी होगी और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई और अल्टरनेटिव आपके पास होगा, वह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, आप खुद किसान व बागवान हैं । जो वहां सेब तोड़ता था, मार्किट में ले जाता था आज उस बागवान पर क्या गुज़र रही होगी, यह आप खुद भलि-भांति जानते हैं क्योंकि आप खुद बागवान हैं। रमेश ध्वाला जी भी बैठे-बैठे सुझाव दे रहे हैं क्योंकि इस बारे में इनको काफी अनुभव है, ये सुझाव दे रहे हैं कि ठेकेदार पर क्लेम ठोका जाए लेकिन मुझे पता है कि इस सम्बन्ध में उनका क्या जवाब आने वाला है। वे बोलेंगे कि अगर डंगे टूट गए हैं तो हम रिस्टोर कर देंगें लेकिन उसका क्या जो उन्होंने पर्यावरण की चीर-फाड़ कर दी है, चीर हरण कर दिया है? उसका क्या जो बड़े-बड़े ढांक आज बागवानों की छतों पर खतरा बन कर बैठे हैं? उसका क्या जो पेयजल योजनाएं टूट गई हैं? आज लोग तीन-तीन किलोमीटर दूर से बाल्टियों और ड्रमों में पानी ढो कर ला रहे हैं? उसका क्या जो वहां सड़कें बनी थी , आज वे सारी अवरुद्ध हो गई हैं? उसका क्या जो

बागवान आज सेब व नाशपाती मार्किट में ले जाना चाहता है लेकिन सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं? मैं पूरे छः दिन तक इस सड़क पर खड़ा हुआ हूं। सड़कें खुलवाई और रात को ब्लास्टिंग करते हैं which is not allowed. बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। और लोग इसमें भी राजनीति करते हैं और सोशल मीडिया में देते हैं कि सड़क नहीं खुल रही। सारे हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कुछ तो सीखो। हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज वहां के लोग भयंकर कष्ट में हैं और मेरा इस नियम के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि मुझे आपकी सरकार, अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है कि वहां के लोगों को न्याय मिलेगा। जो हमारा निवेदन है कि वहां जो पेयजल योजनाएं हैं, वे दुरुस्त हों और जो वहां पर नुक्सान हुआ है, उसका मुआवज़ा मिले। जिसने भी यह नुकसान किया है, उसको दंड मिले वह चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1225/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बरागटा जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। 29 जुलाई, 2018 को अमर उजाला में समाचार भी प्रकाशित हुआ था -"सड़क के मलबे में दबे दर्जनों हरे-भरे पेड़" और उसके माध्यम से इस विषय को ध्यानाकर्षण के रूप में इस माननीय सदन में लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसका काम कैसे शुरू हुआ और इस सड़क में सारी परिस्थितियां किस प्रकार की थी? जब यह काम शुरू हुआ था, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। इस सड़क का काम शुरू करवाने के लिए लगातार लम्बे समय तक आन्दोलन हुआ और वह आन्दोलन जन-

आंदोलन के रूप में उस क्षेत्र में खड़ा हुआ क्योंकि जो चीजें जिस रूप में हो रही थीं, वो जनता को भी स्वीकार्य नहीं थी । आखिरकार उस सड़क का काम शुरू हुआ और उसके बाद वह पूर्ण होने की स्थिति में पहुंचा । अभी हाल ही में वहां पर भारी वर्षा के कारण जो परिस्थिति निर्मित हुई उसके कारण बहुत नुकसान हुआ और इसमें दो राय नहीं है कि जो सारी चीजें जिस रूप में होनी चाहिए थीं, उस रूप में नहीं हुई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

24.8.2018/1230/av-hk/1

मुख्य मंत्री------- जारी

भले ही वहां पर डम्पिंग साइट दोनों जगह पर अप्रूव्ड थी। निहारी और सल्याणा में उन डम्पिंग साइट्स पर उस मलवे को रखने की व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि बरसात के मौसम में वह मलवा नीचे न बहे और गांव व बागीचों को नुकसान न पहुंचाये। इन सारी बातों को लेकर के एहतियात बरतने की जरुरत थी।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:-

इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाया जाता है कि माननीय विधायक श्री नरेन्द्र बरागटा जी के विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-62 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस में अमर उजाला में प्रकाशित समाचार की तिथि 29.7.2018 दर्शाई है जबकि यह समाचार अमर उजाला में दिनांक 12.12.2017 को प्रकाशित हुआ था।

इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जाता है कि सड़क का कार्य मै0 सी0 एण्ड सी0 को आवंटित किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

ठियोग-कोटखाई-खड़ापत्थर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़िकरण का शेष कार्य 0.00 किलोमीटर से 48.00 किलोमीटर को मै0 सी एण्ड सी0 कनस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटिड को अनुबंध पी0डब्ल्यू0-एस0आर0पी0/आर0आई0डी0सी0/प्रोक्योरमैंट-आई0सी0बी0-5/पी0के0जी0-1/2013 द्वारा दिनांक 19.11.2013 को रुपये 179,44,12,269/- के लिए आवंटित किया गया था। प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि 1 जनवरी, 2014 थी और इस काम को पूर्ण करने के लिए दिनांक 30 जून, 2016 निश्चित की गई थी। कार्य प्रगति पर है और दिनांक 31.7.2018 तक 89.74 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 191.64 करोड़ रुपये इस पर व्यय हो चुके हैं। इस परियोजना के पूरे होने की सम्भावित विस्तारित तिथि 31.12.2018 है। ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क का निहारी से सल्याणा का भाग किलोमीटर 37.00 से किलोमीटर 39.00 के मध्य पड़ता है जिसकी कुल लम्बाई

24.8.2018/1230/av-hk/2

दो किलामीटर है। इस भाग में 1.830 किलोमीटर की चौड़ाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा केवल 170 मीटर का कार्य शेष बचा हुआ है जो कि प्रगति पर है। इस सड़क में निहारी से सल्याणा के बीच में सड़क की मिट्टी के भण्डारण के लिए विभाग द्वारा चम्बीकुफर व निहारी में सम्बंधित विभाग की स्वीकृति के उपरांत दो भण्डारण स्थल ठेकेदार को दिए गए हैं जिनकी चेनेज किलोमीटर 36.00 और किलोमीटर 39.00 है। इन्हीं चिन्हित स्थलों पर ठेकेदार द्वारा कटाई से निकले मलवे का भण्डारण किया गया है। जब भी ठेकेदार द्वारा की गई अवहेलना सामने आई है तो विभाग द्वारा परामर्शदाता 1/4 कनस्लटैंट 1/2 के माध्यम से ठेकेदार को समय-समय पर चेतावनी नोटिस दिए गए हैं। इस बारे में यह भी सूचित किया जाता है कि इन डम्पिंग स्थलों पर जो सड़क के कटान के मलवे का भण्डारण किया गया था वहां पर कुछ मिट्टी बरसात में भारी बारिश के दौरान एवं तीखी ढलान होने के कारण नीचे बह गई है। इस कारण जो भी नुकसान होगा उसका निपटारा कांट्रैक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा। जिन लोगों की निजी भूमि का नुकसान हुआ है

श्री टी सी द्वारा जारी

24.08.2018/1235/TCV/HK/1

माननीय मुख्य मंत्री..... जारी

उसकी क्षतिपूर्ति का आकलन संबंधित विभाग से करवा कर नियमानुसार अदायगी की जाएगी। जोकि ठेकेदार द्वारा बीमा कंपनी के माध्यम से देय होगी अन्यथा ठेकेदार को विभाग द्वारा देय राशि से वसूली की जाएगी। ऐसे कुछ प्रभावित परिवारों ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला उठाया है जिसका निपटारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बीमा कंपनी तथा ठेकेदार के माध्यम से ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को लेकर जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि श्रीमती कृष्णा देवी और श्री शेर सिंह दो लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी गये हैं। उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में भी दरख्वास्त है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसका पालन होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि इस सड़क की बहुत लम्बी कहानी है। इसकी डिटेल मैंने देखी है। इसमें वर्ष 2007 में एफ0सी0ए0 का इश्यू था और उसके बाद टेंडर की जो फाइनेंशियल बिड इत्यादि है, ये सारे जांच के विषय हैं। क्योंकि नियमानुसार यह कार्य नहीं हो सकता था लेकिन उसके बावजूद भी टेंडर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को सड़क मिलनी चाहिए और यह हमारी प्राथमिकता रही है। उस दृष्टि से उसमें जो कुछ कार्य करने के थे, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी जो भारी नुकसान हुआ है, वह इस कंपनी के गलत तरीके से काम करनी की वज़ह से हुआ है। इसमें कटिंग जिस प्रकार से होनी थी, उस प्रकार से न करके बहुत ही अग्रैसिव तरीके से कटिंग करके बोल्डर ऐसी जगह रख दिए गए, जहां से उनके नीचे गिरने और नुकसान होने की की बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। इसके अलावा जिन

डम्पिंग साइड का हमने ज़िक्र किया, उसमें एतिहात के तौर पर जो कुछ करना चाहिए था, उसमें कमियां पाई गई है। जैसा मैंने आपके ध्यान में लाया है कि जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो ठेकेदार है, हम उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। ताकि लोगों का जो

24.08.2018/1235/TCV/HK/2

नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार से भी उस ठेकेदार द्वारा की गई कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों की जो यथासंभव सहायता की जा सकती है, उसको करने की कोशिश करेंगे।

24.08.2018/1235/TCV/HK/3

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री अनिरूद्ध सिंह जी नियम-130 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार हैः-

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु यह सदन विचार करे।"

इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री नरेन्द्र बरागटा , श्री मुकेश अग्निहोत्री व श्री बलवीर सिंह जी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे भी इस चर्चा में भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही मुझे कुल 16 नाम दोनों पक्षों से इस चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त हुए हैं और सभी को बोलने का समय देना है। इसलिए मैं जो इसके मूवर है, उनको 10 मिनट और शेष सभी सदस्यों को 8-8 मिनट का समय निर्धारित करता हूं। जिससे लगभग 2 घंटा 15 मिनट में ये चर्चा समाप्त होने के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

24-08-2018/1240/NS/YK/1

अध्यक्ष-----जारी

मेरा अनुरोध है कि कोई भी सदस्य अपने समय को एक्सीड न करें, तब हम इस चर्चा को पूरा कर सकेंगे अन्यथा मुझे बार-बार घंटी बजानी पड़ेगी। सबसे पहले चर्चा में माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी भाग लेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। प्रदेश में अगस्त महीने में जो बारिश हुई है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वैसे तो हर वर्ष बारिश होती है लेकिन 13 अगस्त को हुई बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बारिश से न केवल शिमला जिले में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिला है। हमारे कई बुजुर्ग 80-90 साल के हो चुके हैं और कई सौ साल के हो रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी बारिश शायद कभी नहीं देखी होगी। यह बारिश रात को 2.00 बज़े से शुरू हुई और दिन के 11.00 बज़े तक भारी वर्षा होती रही। इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान जिला शिमला, कांगड़ा में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। लगभग सभी सड़कें चाहे वे स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हैं या चाहे गांव के पंचायतों की

सड़कें थी, उस दिन एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जो खुली रही हो। इस बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई सड़कें एक हफ्ते बाद खुली हैं। ये खबरें अख़बारों में भी आती रही हैं। बसों के 253 रूट बंद हो गये हैं। यहां तक कि जो हमारे मुख्य नेशनल हाईवे हैं जैसे शिमला-कालका, शिमला-धर्मशाला, शिमला-मनाली और शिमला से किन्नौर सड़कें भारी बरसात के कारण बंद रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क ऐवरसन्नी-भौंट रोड जो बाया गोल्चा है, भारी बारिश के कारण बंद हो गई है। जिस समय यह सड़क बंद हुई थी, हमने संबंधित अधिकारियों को कहा था कि यह सड़क खड्ड के नज़दीक है और इस सड़क का सर्वे किसी और जगह से हुआ है जोकि हाईट पर थी। अब यह सड़क बिल्कुल खड्ड बन गई है। वहां पर अभी अधिकारी मौका देखने गये हुए थे लेकिन उनका जवाब था कि इतना बज़ट विभाग के पास नहीं है। यह सड़क "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" में बनी है। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क विभाग ने ही गलत बनाई है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इसे शीघ्रातिशीघ्र रीस्टोर करके इस रूट पर बसें

24-08-2018/1240/NS/YK/2

चलाई जायें। मैं मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि गांव वालों ने अपने पैसों से इस रोड को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल किया है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष महोदय, ढली-मैहली बाईपास उस दिन से ले करके जिस दिन यह भारी बारिश हुई है, आठ बार बंद हो चुका है। उस दिन भी 3-4 जगह इतना ज्यादा भूस्खलन हुआ है। एक प्वाईंट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, जो हर वर्ष बरसात में 3-4 बार बंद होता है। इसके लिए हमने पिछली सरकार में धरना प्रर्दशन भी किया था और उस समय के जिलाधीश महोदय और हिमुडा के सी0ई0ओ0 ने आश्वासन दिया था कि इस मलबे को हटाया जायेगा। ....(व्यवधान).....

अध्यक्षः प्लीज़ आप अपनी बात कहें।

श्री अनिरूद्ध सिंहः इस साल भी हिमुडा वालों ने आश्वासन दिया था कि हम पैसे देंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, लेकिन आज तक इसके लिए कोई पैसे नहीं दिये गये हैं। इस

बार भी वहां पर तीन गाड़ियां दबी हुई हैं और तीन बार सड़क बंद हो चुकी है। मल्याणा के पास बारिश के पांच दिन बाद इतना बड़ा पहाड़ गिरा कि अधिकारी भी सोच रहे थे कि इसको कैसे हटायेंगे क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा मलबा था कि नेशनल हाईवे भी बंद रहा और शिमला शहर के अंदर से रात को वन-वे करके सारे सेब के ट्रक क्रॉस करवाये गये। शिमला में एक समस्या यह भी है कि यहां पर कोई डम्पिंग साईट नहीं है और यह बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपने खेतों में मलबा नहीं फैंकने देते हैं और नीचे भवन बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि शिमला शहर के अंदर एक डम्पिंग साईट क्रिएट की जाए जोकि बाद में ग्राउंड के रूप में भी काम आये। हम सबको पता है कि दिल्ली में डम्पिंग साईट में कूड़ा डाल करके पार्क बना दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मिट्टी भी ऐसी जगह डम्प की जाए ताकि आने वाले समय में एक बड़ा ग्राउंड बन सके। इसके अलावा मैं पुलों के बारे में बताना चाहूंगा। गांव में कोई भी ऐसा पुल जो पंचायतों या खंड स्तरों पर बना है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस भारी बारिश से नहीं रहे हैं, वे सारे-के-सारे बह गये हैं। शत-प्रतिशत टूट चुके हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

24.08.2018/1245/RKS/Yk-1

श्री अनिरूद्ध सिंह... जारी

इनके मुआवजे के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी पहल करें। जो बड़े पुल हैं, जैसे साधुपुल, कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से सोलन को कनैक्ट करता है वह भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पुल में बड़ी गाड़ियों की आवाजाही काफी समय से बंद है। मेरा निवेदन है कि इस पुल को भी जल्द-से-जल्द बहाल किया जाए। बारिश के कारण कम-से-कम 80-100 गाड़ियां शिमला शहर और कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र में दबी हुई हैं। बहुत से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। In the interest of public मैं एक बात कहना चाहूंगा- पहले मृत्यु पर सरकार एक लाख रुपये मुआवजा देती थी। बाद में यह मुआवजा डेढ़ लाख रुपये हुआ और अब साढ़े चार लाख रुपये हो गया है। लेकिन घरों के क्षतिग्रस्त होने या आग लगने पर 70-75 हजार

रुपये ही दिए जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए क्योंकि 20, 50 व 70 हजार रुपये में आजकल एक तिरपाल भी नहीं आती।

अभी हमारे माननीय सदस्य बरागटा जी ने पेड़ों के बारे में एक विधान सभा प्रश्न पूछा था। आजकल शिमला शहर के आस-पास बहुत से पेड़ गिर रहे हैं और इन पेड़ों की उम्र भी काफी हो चुकी है। अभी एक हफ्ता पहले विधान सभा के बाहर बहुत बड़ा डंगा गिरा । उस समय इत्तफ़ाक से मैं, पठानिया जी और श्री मोहन लाल ब्राक्टा वहां पर मौजूद थे। हम लोगों ने इस डंगे की लाइव रिकॉर्डिंग भी की जिसमें 6-7 पेड़ नीचे गिरे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सैक्शन-133 CrPC में एस.डी.एम. के पास ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरह पॉवर होती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि पिछले एक साल में शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण एस.डी.एम. ने सैक्शन-133 Cr.PC में कितनी परमिशन्ज म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के अंडर दी? आज घरों व पेड़ों को काफी नुकसान हो रहा है। शकराला में घर के ऊपर पेड़ गिर गया, उसके मुआवजे की एप्लीकेशन दी गई परंतु प्रशासन कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यदि हाथ बंधे हुए हैं तो 133 Cr.PC क्यों है और पिछले एक साल में 133 Cr.PC में कितनी परमिशन्ज दी गई हैं?

24.08.2018/1245/RKS/Yk-2

हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

मैं आई.पी.एच. पर भी कुछ बोलना चाहूंगा। शिमला जिला में ही आई.पी. एच. विभाग का कम-से-कम 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शिमला शहर को गुम्मा खड्ड, कोटी-ब्रांडी व अश्वनी खड्ड से पानी आता है। कोटी-ब्रांडी की स्कीम पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अश्वनी खड्ड के सभी फिल्टर टैंक बह गए हैं। शिमला ग्रामीण के लिए

तैयार घंडल स्कीम के फिल्टर टैंक्स भी बह चुके हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आई.पी.एच. के नुकसान के लिए भी जल्द-से-जल्द राशि बहाल की जाए।

फागू-चियोग सड़क का भी बूरा हाल है। बारिश के कारण ऐसा लगता है कि उसमें नाला ही बह रहा हो। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने पिछले विधान सभा सत्र में यह आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क के लिए इसी बजट में 57 करोड़ रुपये स्वीकृत करेंगे। डिपार्टमैंट ने पहले ही एस्टिमेट सब्मिट करवा दिया है परंतु दुःख की बात है कि आज तक इस सड़क के लिए 57 पैसे भी नहीं मिले। इस सड़क के लिए जल्दी-से-जल्दी राशि स्वीकृत की जाए ताकि लोग इस सड़क का फायदा उठा सके।

समाचार-पत्र में एक खबर छपी थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी एक स्टेटमैंट दी थी कि केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह खबर प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया दोनों में प्रकाशित हुई। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एक घोषणा थी या यह राशि प्रदेश सरकार को मिल चुकी है? यदि यह राशि मिल चुकी है तो इस राशि का आबंटन कैसे किया जा रहा है? क्या यह राशि जिलावार आबंटित की जा रहा है या नुकसान के हिसाब से आबंटित की जा रही है?

श्री बी0एस0 द्वारा.... जारी

24.08.2018/1250/बी.एस/ए.जी/-1

श्री अनिरूद्ध सिंह जारी...

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज केरल में 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे भी हिमाचल प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ होगा। हम सभी लोग केरल की त्रासदी के लिए बहुत गम्भीर हैं। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के लिए भी हमें गम्भीर होना चाहिए। इस बारे में सही समय

पर सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1250/बी.एस/एच.के/-2

श्री हर्षवर्धन चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा "प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु यह सदन विचार करे।" इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मेरा भी यही प्रस्ताव था। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दो महीनों में हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे यह सड़के हैं, चाहे आई.पी.एच. विभाग की स्कीमें हैं और चाहे निजी संपत्ति है, सभी का नुकसान हुआ है। यह सही है कि बरसात हर वर्ष होती है और फिर समाप्त जो जाती है। थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता था। परंतु इस बार की बरसात ने जो नुकसान किया है वह बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया है। प्रदेश में इस बार वर्षा के कारण दो दर्जन लोगों की जानें चली गई हैं। यह बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पर अवश्य गहनता से विचार होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामने वाले बैंचिज देख रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी और दो अन्य मंत्री माननीय सदन में मौजूद हैं। यह विषय कई विभागों से संबन्धित है। परंतु उन विभागों से संबन्धित मंत्री यहां मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री सदन में बैठे हैं, इसलिए आपकी बात को गौर से सुना जाएगा।

श्री हर्षवर्धन चौहान : सरकार को ऐसे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय श्री नरेन्द्र बरागटा जी सड़कों के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसमें पूर्व की सरकार के सम्बन्ध में भी जिक्र हुआ, परंतु हमारी सरकार को गए

एक वर्ष हो चुका है। यह 18.08.2018 की खबर है कि ठियोग-हार्टकोटी हाइवे अभी तक बंद पड़ा है। 13.08.2018 को सड़क बंद होती है और पांच दिन के बाद भी वह सड़क नहीं खोली जाती, इसमें किसका दोष है। आदरणी बरागटा जी ने ठीक कहा कि हजारों की तादाद में जो किसान है, जो बागवान है वे परेशान हैं। सड़के आज भी प्रदेश में बंद पड़ी हैं। सरकार ने अवश्य सड़कों को खोलने के प्रयास किए हैं, आपने सड़के भी खोली हैं। 12 व

24.08.2018/1250/बी.एस/एच.के/-3

13.08.2018 को दो दिन जो भारी बरसात हुई है, उस बारे में "अमर उजाला" अखबार लिखता है कि "923 सड़कें बंद" "एक दर्जन पुल ध्वस्त" "कालका शिमला रेवले ट्रेक पर 26 गाड़ियां रद्द" " भाजपा नेता समेत 16 की मौत" अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के जिलों में नुकसान हुआ है। आज प्रदेश में फोर लेन बन रहे हैं। परवाणु से सोलन तक फोर लेन की हालत आप देख रहे हैं, चलना मुश्किल हो गया है। वहां पहाड़ी की तरफ तो वाहन चल ही नहीं पा रहे हैं। हम पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हैं, हम पहाड़ों के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश को इसका ख़ामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी पठानकोट- मण्डी नेशनल हाइवे बहुत समय तक बंद रही, उसके बाद कीर्तपुर-मनाली नेशनल हाइवे बहुत समय तक बंद रहा। अध्यक्ष महोदय, आज भी हिमाचल प्रदेश में डेढ़ सौ के करीब सड़के बंद पड़ी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सड़कों को खोलने का कार्य तेजी से किया जाए। ताकि किसानों और बागवानों को इसका नुकसान न उठाना पड़े। हिमाचल प्रदेश में सड़कों को लगभग 6 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । आई.पी.एच. विभाग की 2,746 स्कीमों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे 117 करोड़ रुपये का आई.पी.एच. विभाग को नुकसान हुआ है। बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है । मेरा अपना मानना है कि हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश से एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी

24.3.2018.1255.DT/AG /-1

श्री हर्षवर्धन चौहान... जारी

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे बैठक की और 95 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि जिलों को रिलीज़ की, जोकि बहुत कम राशी है। मुझे लगता है कि एक जिले को 3 या 4 करोड़ से ज्यादा पैसा नही जाएगा। केन्द्र में भाजपा की सरकार है हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है। मगर केन्द्र सरकार ने अभी हिमाचल की कोई सुध नहीं ली है कि हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कैसे की जाए। केरल में नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्र की टीम गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार से कहा भी है या नहीं। केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई चिन्ता नहीं की है, यह भी एक चिन्ता का विषय है। केन्द्र सरकार को राहत के तौर पर कुछ पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरंत देना चाहिए था ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तेज़ी से की जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह आंकडा लोक निर्माण विभाग की सडकों का है परंतु हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ब्लोकों द्वारा बनाई गई हैं। वे सड़कें भी बाधित है उनको कैसे खोला जाएगा और उनको लिए कैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सड़कों पर भी विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारा रीलिफ मैन्यूअल बहुत पुराना हो गया है। उसमें संशोधन करने की जरूरत है। जो लोगों का नुकसान होता है उसमें बहुत कम प्रावधान है। उसमें मैक्सिमम 40 हजार और not more than 20% of the loss. हमारे रेवेन्यू के अधिकारी तहसीलदार, SDM राहत के तौर पर किसी को 4 हजार , किसी को 8 हजार दे रहे हैं, किसी को 10 हज़ार दे रहे है। वह कई बार मज़ाका हो जाता है। अभी जैसे अनिरूद्व सिंह जी कहा की यह राशि बहुत थोड़ी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय लोगों की भरपाई करने के

लिए इसमें भी कदम उठाने की जरूरत है। इस रिलिफ फंड में संशोधन किया जाए और इसकी राशी को बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। जैसे बरागटा जी ने अभी पेड़ो का जिक्र किया जिनके घर सड़क से

24.3.2018.1255.DT/AG /-2

ऊपर हैं या नीचे है उनको भारी नुक्सान हुआ है। आप अभी हाटकोटी सड़क की बात कर रहे थे। मेरी ससुराल रोहडू में है और रोहडू से शिमला तीन घंटों में आया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 90 प्रतिशत वर्क खत्म हो चुका है। 90 प्रतिशत वर्क तो एक साल पहले खत्म हो चुका था। निहारी के पास जहां कटिंग हो रही है वही वाला पोंसन रहा गया है। आज जहां भी रोडज़ बन रही है, जहां डंपिंग साइट चिन्हित की गई है वहां पर ठेकेदार मलबा नहीं फैंकते हैं। वे ऊपर से कटिंग कर नीचे को फैंकते हैं और जब बरसात आती है तो वह मलबा लोगों के घरों को नुकसान करता है। यह भी एक चिंता का विषय है कि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ न की जाए और जो ठेकेदार नुकसान पहुंचाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत से डैम बन रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। गिरी वाटर सप्लाई स्कीम का पानी बाता नदी में डाल दिया जाता है। जब बरसात आती है तो बाता नदी का पानी पावंटा वैली को काटते हुए जाता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय मैं वाइंड अप कर रहा हूं।

श्री एन जी द्वारा जारी ..

24/8/2018/1300/डी0सी0/एन0जी0-1

श्री हर्ष वर्धन चौहान ….. जारी

और बाता नदी की जो चैनेलाईजेशन हुई है वो 25 प्रतिशत भी नहीं हुई है। जो लोगों की fertile ज़मीन है वो कट रही है। इसलिए उस ओर भी चिन्ता करने की जरूरत है। बाता नदी के चैनलाईज़ेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। ताकि जो हमारे किसान है उनकी ज़मीन को नुकसान न हो। सरकार ने सुस्ती दिखाई है। लोगों को immediate राहत नहीं दी है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। Natural Calamities में आप चार लाख रूपये देते हो और immediate relief के तौर में हम दस या पन्द्रह हज़ार रूपये देते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है की जहां पर Natural Calamities की वजह से मृत्यु हुई है उनको तुरन्त राहत राशि प्रदान की जाए । अगर माननीय मुख्य मन्त्री उचित समझते हैं तो एक प्रस्ताव केन्द्र से मदद प्राप्त करने के लिए इस माननीय सदन में लाया जाए। प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है उस बारे में इस माननीय सदन में चर्चा की जाए और केन्द्र सरकार को भेजा जाए ताकि जो उचित मुआवज़ा है वह केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश को दे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां नुकसान हुआ है, पुल टूटे हैं सड़के टूटी हैं, पेय जल की स्कीमें टूट गई हैं, बहुत सारे स्थानों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है।, बिजली के पोल गिर गये हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कई स्थान ऐसे हैं जहां कई दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। जहां-जहां भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार गम्भीरता से सोचे। कोई ठोस नीति लाये। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती हैा

24/08/2018/1405/RG/HK/1

(विधान सभा की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः 2.05 बजे आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में श्री नरेन्द्र बरागटा जी भाग लेंगे। आठ मिनट का समय है।

श्री नरेन्द्र बरागटा : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। नियम-130 के अन्तर्गत मैं भी अपनी कुछ समस्याओं और मुद्दों को लेकर अपनी बात यहां रखना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पीछे तीन दिन की बारिश पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान करके चली गई। इससे कहीं जानें भी चली गईं, देश में भी यही हुआ और हमारे प्रदेश में भी कई स्थानों पर बहुत भयंकर किस्म की घटनाएं घटीं। इस भयंकर बारिश से पशुधन का नुकसान तो हुआ ही। विशेष करके जैसी सूचना मिली है उसके अनुसार सड़कों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश में कई जगह ऐसी भी थीं जहां घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। बगीचों में पानी चला गया। खास करके अपर शिमला में लगातार बारिश ने काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अख़बार की रिपोर्टिंग देख रहा था तो कई वर्षों बाद इतनी वर्षा शिमला में हुई है और कोटखाई उसमें सबसे नंबर-1 पर है जहां बहुत अधिक बारिश हुई है। ऐसा पहली बार देखा गया। इसके कारण से बहुत सारी पेय जल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, कई बिजली के खम्भे गिर गए, कई तारें टूट गईं और कई जगह ट्रांसफॉमर्ज़ इत्यादि को भी बहुत नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, बागवानों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए प्रदेश में अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का और विभाग के सब अधिकारियों का धन्यवाद करना है कि जिस मुस्तैदी के साथ सड़कों को रेस्टोर किया गया है, इसके लिए मैं दूर का उदाहरण तो नहीं दूंगा लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं भी मॉनीटरिंग करता रहा। हमारे डिवीजन में इन तीनों की बारिश से लगभग 27 सड़कें अवरूद्ध हुई थीं। लेकिन विभाग को जैसे ही मौका मिला तो 25 सड़कें तो एक दिन में सारी मशीनरी लगाकर चालू कर दी गईं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो सेब उत्पादक हैं उनको इसका बहुत ज्यादा ख़ामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ा और समय पर वहां से सेब निकलना शुरू हो गया। इसके अलावा दो-तीन सड़कें ऐसी थीं जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कहीं डंगे लगने थे, इसलिए वे किसी कारण से रह गईं। उनमें भी हमारे अधिकारियों

ने अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और लोक निर्माण विभाग के सारे अधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2018/1410/MS/AG/1

श्री नरेन्द्र बरागटा जारी------

जिला शिमला में हर बार जब भी अधिक वर्षा होती है तो यहां बहुत नुकसान होता है। सदन में रामपुर चुनाव क्षेत्र के विधायक भी मौजूद हैं, ये भी शायद अपनी बात को रखेंगे। इनके क्षेत्र में कूट करके एक जगह है जहां पर बादल फट गया। बादल फटने की घटना प्राकृतिक क्रूरता के रूप में आती है जिसमें भागने तक का मौका नहीं मिलता है। इस तरह से कई जगह बादल फटे हैं। ठियोग में जहां लगभग 40 सम्पर्क सड़कें अवरूद्ध रहीं, उस बारे में राकेश सिंघा जी स्वयं प्रकाश डालेंगे। रामपुर, चौपाल, जुब्बल-कोटखाई, रोहडू और ठियोग में मुस्तैदी के साथ काम हुआ और मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पेयजल योजनाएं सड़कों के कारण से अवरूद्ध हो गईं या डैमेज हो गईं, उनको तुरन्त ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जहां-जहां सड़कें अवरूद्ध रह गई हैं वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने अभी नियम-62 के अंतर्गत जो बातें कही थीं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन मुख्य मंत्री जी ने छैला से लेकर रोहडू तक सड़क ठीक चले, इसके लिए अधिकारियों से व्हट्स-ऐप पर ये स्वयं जानकारी लेते रहे और मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग करता रहा हूं। वहां पर पुलिस की फोर्स इन्होंने भारी संख्या में लगाई हुई है और उनको वायरलैस से लैस करके रखा हुआ है ताकि अगर एकदम कहीं कोई ल्हासा आ जाता है या अन्य कोई घटना घट जाती है तो इस पार और उस पार गाड़ियों/लोगों को रोका जा सके और यदि कोई बीमार हो जाता है या अन्य कोई समस्या आती है तो तुरन्त समाधान हो जाए। मुझे मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना है कि इनके दिशा-निर्देश से कि कहीं जाम न

लगे, उसकी वायरलैस के माध्यम से जगह-जगह व्यवस्था की गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है।

अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं सारी बातें नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कह चुका हूं। मैं चौहान साहब को थोड़ा करैक्ट करना चाहता था ताकि रिकॉर्ड में बात करैक्ट हो जाती लेकिन इस समय वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि

24/08/2018/1410/MS/AG/2

ठियोग हाटकोटी रोड लगभग पांच दिन अवरूद्ध रहा है। मैंने कहा कि मैं छः दिन तो स्वयं उस एरिये में था। वे तो हमारे जमाई हैं इसलिए रोहडू से ही फोन पर बात कर लेते। यहां पर गलत रिपोर्टिंग कर देना अच्छी बात नहीं है इसलिए वे तथ्यों को थोड़ा सा करैक्ट कर लें। सड़कें जरूर अवरूद्ध हुई हैं। -(व्यवधान)-इसीलिए मैंने उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है। यहां पर माननीय सदस्य मोहन लाल जी बैठे नहीं है। उनसे तो मुझे थोड़ा गिला भी है और यदि वे यहां उपस्थित होते तो मैं उनसे बात भी कर लेता। सड़क का ठेका कोई जुब्बल-कोटखाई के विधायक का नहीं है। यह सड़क चार चुनाव क्षेत्रों से होकर जाती है। हमें वहां पर मोहन लाल जी तो कहीं दिखे ही नहीं। उनको वहां आना चाहिए ताकि हम मिल करके मुख्य मंत्री जी से बात कर सके लेकिन वे कहीं दिखते ही नहीं हैं। वे भी तो रोहडू से होकर के आते हैं। चलो, कोई बात नहीं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे मेरे मित्र हैं इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि थोड़ी सख्ती बरतिए क्योंकि एक और एक ग्यारह बनते हैं इसलिए यदि साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पिछली बार कांग्रेस के समय में लाल बत्ती लगाने की आज्ञा थी तो वे लाल बत्ती की गाड़ी लेकर किसी भी दुकान में घुस जाते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि बाहर निकलो, आपकी सरकार है इसलिए कुछ काम करवाओ। यहां सड़कें अवरूद्ध हो गई हैं इसलिए राजा साहब से बात करो। तो इसमें डरने की बात नहीं है। हम विधायक हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। आज तो ऐसी सरकार है कि ये किसान/बागवान स्वयं हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो ये स्वयं इंटरवीन करते हैं। मैंने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में काफी बातें कवर कर दी हैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुख्य मंत्री जी जो मैंने कुछ बातें यहां पर अध्यक्ष

महोदय के माध्यम से रखी हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि आप इससे अवगत हैं। मैं दुबारा से लोक निर्माण विभाग और बाकी विभागों को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अंत में, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि 56 ट्रांसफॉर्मर्ज दो दिन खराब रहे और तीसरे दिन सारे-के-सारे ट्रांसफॉर्मर्ज रिपेयर हो गए। वैसे ही पेयजल योजनाएं भी रिपेयर हो गईं। इसी तरह से हमारी सड़कें भी तुरन्त दो दिन के अंदर ही 80 से 90 परसेंट ठीक हो गईं और अब तो लगभग नॉर्मल हो गई हैं। इसके लिए मुख्य मंत्री जी और इनके अधिकारी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।

अगले वक्ता श्री जे0के0 द्वारा---

24.08.2018/1415/जेके/वाईके/1

अध्यक्षः श्री मुकेश अग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। बरसात से जो प्रदेश को नुकसान हुआ, प्रदेश की सम्पत्ति को नुकसान हुआ और जान-माल को नुकसान हुआ, मैं पहले ही सपष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह प्रदेश के लोगों और विकास से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें सरकार जो भी कदम उठाती है, हम और हमारा दल उसमें सहयोग देने के लिए हर तरह से तैयार है। बारिश हुई और बहुत अधिक नुकसान हुआ। हालांकि बारिश थोड़े दिन ही हुई और नुकसान ज्यादा हो गया। लगभग दो दर्जन लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसके आस-पास का आंकड़ा हो सकता है। उन परिवारों से हमारी सहानुभूति है। अध्यक्ष महोदय, बरसात के मौसम में सरकार की तैयारी की बात मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा। चाहे कोई भी सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । ऐसे मौसम में सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए? जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी है उसके मुख्य मंत्री जी खुद चेयरमैन हैं, वह ओवर ऑल डिजास्टर को प्रदेश में देखती हैं। मैं, मुख्य मंत्री जी

से जानना चाहूंगा कि यह बैठक आपने कब की और कितने दिन पहले की? उसके बाद स्टेट एग्ज़ेक्युटिव कमेटी, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम करती है जिसमें डिपार्टमैंटल सेक्रेटरीज और दूसरे विभागों के एच0ओ0डीज़ व रैगुलर मैम्बर्ज़ होते हैं। यह बैठक सरकार ने कब की? तीसरे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमेटीज़ होती हैं जो डी0सीज़0 की अध्यक्षता में काम करती हैं। क्या आपने चैक किया कि आपके डी0सीज़0 ने ये बैठकें कब की और कब आपने उनको इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा? इन तीनों स्तरों पर इसकी तैयारी के लिए बैठकें होनी चाहिए थी क्योंकि अब तो मौसम की तुरन्त जानकारी मिल जाती है। अगर आप फील्ड में दो-तीन-चार दिन पहले इंटिमेट करेंगे कि मौसम खराब होने जा रहा है तो प्रशासन उसके लिए तैयारी नहीं कर पाएगा और

24.08.2018/1415/जेके/वाईके/2

बैठकें भी नहीं करेगा। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अपना प्रशासन तंत्र दुरुस्त करें। ये बैठकें हर जिला में समय पर हों। हर जिले की मीटिंग की मॉनिटरिंग की जाए कि उन्होंने क्या-क्या किया है। आनन-फानन में जो काम किए या एक हफ्ते के अन्दर या दो दिन पहले या चार दिन पहले, इसकी एक लम्बी तैयारी होनी चाहिए । शिमला में पानी का संकट क्यों हुआ? उस समय आप म्युनिसिपल कमेटी में अपने शीर्ष अफसरों को भेज रहे थे। आपके टॉप ऑफिसर्ज़ म्युनिसिपल कमेटी में बैठ रहे थे। अगर तैयारी की होती तो शायद यह संकट न आता। हमारे साथी बरागटा जी ने कहा कि सरकार बहुत अच्छे से तैयार थी और इससे पहले लगभग ऐसे ही मुद्दे पर इन्होंने जो सड़कों की हालत खराब हुई है, उनकी दास्तां बयां की। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आप कालका-शिमला सड़क को देख लीजिए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2018/1420/SS-YK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी उसकी दूसरी साइड खुल पायेगी। न ही वहां पर इतनी मशीनरी लगी हुई है कि ऐसा लगे कि आप उसको जल्दी खोलने की कोई सोच बनाए हुए हैं। वह फोर-वे करते-करते वन-वे में बदल गया है। अगर इस ढंग से काम होगा तो अगले दस साल तक वह वन-वे ही रहेगा। पूरा मलबा नीचे आ गया। आप कहेंगे कि आपके समय में यह सड़क बनी। उन्होंने unscientific किया। वह सड़क किसी के भी समय में बनी, अगर उन्होंने काम किया, सही किया या गलत किया लेकिन पहाड़ हर बारिश में नीचे आयेगा। उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए आप कब वहां पर पूरी मशीनरी भेजेंगे? कुमारहट्टी से लेकर टिम्बरट्रेल तक पूरा-का-पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। पूरा-का-पूरा मलबा नीचे आ गया है। उसको दुरूस्त करना निहायत ज़रूरी है। आज मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और मैंने अखबार में देखा है कि आपने हाई कोर्ट की सड़क को खोलने के लिए कदम उठाए हैं। वह तो राजधानी की सड़क है जिससे मुख्य मंत्री गुजरते हैं। जिससे जजिज़ गुजरते हैं। जिससे सारी ब्यूरोक्रेसी गुजरती है। वहां पर एम0एल0ए0 होस्टल है। एम0एल0ए0 होस्टल से लेकर अगर हाई कोर्ट की सड़क भी एक या डेढ़ महीना बंद रहेगी तो कैसे काम चलेगा! वह बिल्कुल सैंट्रल सड़क है। शहर की लाइफ-लाइन है। ये जो सड़के हैं इनमें बरसात से नुकसान हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। सही आंकड़ा तो माननीय मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे कि प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, कितने जान-माल की हानि हुई है। लेकिन इस स्थिति से तेजी से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। इसके लिए आपने सैंटर से कितना पैसा मांगा है? जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्या आपने कोई क्लेम बनाया है? कितने का क्लेम बना और कितने का आपने सैंटर को भेजा? ठीक है जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि केरल का आकार बड़ा है लेकिन हिमाचल का भी हजार, डेढ़ हजार या दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। आपकी केन्द्र में सरकार है, आप उनसे पैसा मांगिये। जल्दी-से-जल्दी पैसा आए। उनका दल हिमाचल प्रदेश में कब आ रहा है? क्या रेवेन्यू ऑफिसर्ज़ की कोई

बातचीत हुई कि दिल्ली से टीम आ करके पूरे प्रदेश में मूल्यांकन करे कि कितना नुकसान हुआ है और कितनी मदद हुई है। एक बयान मुख्य मंत्री जी का ज़रूर आया कि 96-97 करोड़ रुपये की एक किस्त जारी की

24.08.2018/1420/SS-YK/2

है। लेकिन जिन लोगों की जानें गई हैं क्या उनको आपने पैसा वितरित कर दिया? जिन लोगों के मकान गिरे हैं या जिनका छोटा नुकसान भी हुआ है, मैं देख रहा था कि श्री राजेन्द्र राणा जी के निर्वाचन क्षेत्र सुजानपुर में पूर्व मुख्य मंत्री, धूमल साहब एक-एक हजार रुपये के चैक बांट रहे थे। अब आप बताओ कि आप इतनी बड़ी शख्सियत से एक-एक हजार रुपये का चैक बंटवा रहे हो! कोई राहत की राशि तरीके से बंटवाई जाए। सही ढंग से लोगों की मदद की जाए ताकि लोगों की एक्चुअल ज़रूरत पूरी हो सके। आप 96 करोड़ रुपया जारी कर देंगे लेकिन अगर पैसा फील्ड में नहीं लगेगा तो उसका क्या फायदा होगा? इसलिए केन्द्र से जो मदद लानी है वह लाएं। कुल्लू में एक गौशाला पूरी-की-पूरी बह गई। हमारे साथी, सुन्दर सिंह ठाकुर जी अपने साथ एक वीडियो लाए थे। कहते हैं कि 62 गायें बह गईं। पूरी गौशाला बह गई। आखिर कैसे वहां पर गौशाला बनी? जब वहां पानी आ रहा था तो वहां से गऊओं को क्यों नहीं हटाया गया? यह बजौरा की बात है। अगर आप वीडियो देखें तो यह बहुत ही दर्दनाक और भयानक वीडियो है। बरसात के मौसम को हम किसी भी ढंग से राजनीति की दृष्टि से आंकना नहीं चाहते। हम इसमें आपके साथ हैं। लेकिन अपनी पेस बढ़ाईये। अभी भी कह रहे हैं कि पौने 200 के आस-पास सड़कें बंद हैं। एक दिन तो आंकड़ा आया था कि एक हजार के आस-पास सड़कें अवरूद्ध हुई हैं और 1100 या 1200 करोड़ रुपये का नुकसान बताया था।

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2018/1425/केएस/एजी/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी---

लेकिन आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को थोड़ा चुस्त करें ताकि मॉनसून के सीज़न में हिमाचल के लोगों को राहत मिलती रहे,यही मेरा सरकार से आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1425/केएस/एजी/2

अध्यक्षः श्री बलबीर सिंह जी।

श्री बलबीर सिंहः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है उसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र चिंतपुरनी में भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां गांव में कई कच्चे घर ढह गए हैं। कई लोगों की पशुशालाएं ढह गई हैं। पिछले वर्ष भी ग्राम पंचायत ज्वार में पंगलू नामक गांव में बादल फटे थे । उसकी वजह से परागपुर विधान सभा क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ था परन्तु पंगलू में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारी सरकार नहीं थी परन्तु उस वक्त की सरकार ने पिक एण्ड चूज़ करके लोगों को नुकसान की भरपाई की थी। वहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार है। उसकी 6 बकरियां मलबे में दब गई थी। मैंने पिछले वर्ष भी अपनी जेब से उसकी सहायता की थी परन्तु जब वह सरकार के पास सहायता लेने के लिए गया, मैंने भी डिमांड की तो उस वक्त के विधायक ने यह कहा कि यह बी.जे.पी. के व्यक्ति से बात करवाता है इसलिए इसकी कोई सहायता न की जाए।

इस वर्ष भी पंगलू और साथ में नारी गांव में बहुत नुकसान हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी करवाई जाए। इसी तरह से ग्राम पंचायत घंगरेट भी सारा पहाड़ी गांव है। थोड़ी सी बारीश होने पर भी वहां पर किसी न किसी व्यक्ति का नुकसान हो ही जाता है। परन्तु इस बार वहां पर चार घर मलबे में बह गए हैं और उन घरों के ढहने के बाद वहां पर लगभग 12-13 घरों को खतरा पैदा हो गया है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उन घरों को बचाने के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए। इसी तरह से एक ग्राम पंचायत जवाल है। दुर्भाग्य है कि यह

दलित बस्ति है और पुराने समय से ही दलितों को वहां पर बसने के लिए मज़बूर किया गया जो कि गांव की खुड्डा लाइन हुआ करती थी। यही कारण है कि आग लगती है तो भी वहीं पर लगती है, वर्षा से नुकसान भी वहीं पर होता है। अध्यक्ष महोदय, इस गांव में कम से कम 25 घर है और यह पहाड़ी पर है। हर वर्ष वहां पर भारी वर्षा के कारण नुकसान होता है । इस बार भी लगभग 6-7 घरों को लकड़ी के डंडों से सहारा दे कर खड़ा रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार

24.08.2018/1425/केएस/एजी/3

से निवेदन है कि इन घरों को बचाने की दिशा में भी जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएं। वैसे मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जब से भरवाईं में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का डिविज़न खुला है, यह पहला वर्ष है कि उस विभाग को उस डिविज़न में इस सरकार ने लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये दे कर सड़कों की दशा सुधारने के प्रयास किए हैं। परन्तु मुख्य मंत्री जी साढ़े चार करोड़ रुपया पिछली सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों से एडवांस में काम करवाया था। हमने तो इनका कर्जा चुकाया है । अब 4 करोड़ से गगरेट विधान सभा क्षेत्र और चिन्तपूरनी विधान सभा क्षेत्र में काम पूरा नहीं हो पाया है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उस डिविज़न में भी अति-शीघ्र कुछ न कुछ और सहायता की जाए। वैसे तो हमने सड़कें बन्द नहीं होने दी और दो दिन में ही वहां पर विभाग ने सारी सड़कें खोल दी थी परन्तु कई जगह डंगे बैठ गए हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए जल्दी से जल्दी धनराशि मुहैया करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1425/केएस/एजी/4

अध्यक्षः श्री इन्द्र सिंह।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट): अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत प्रस्ताव पर इस माननीय सदन में जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, क्लाइमैटिक चेंज और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.8.2018/1430/AV-AG/1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)-------- क्रमागत

ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी प्रोब्लम है तथा इस चेंज के एडवर्स इफैक्ट्स की वजह से हम जो ख़ामियाजा भुगत रहे हैं वह अभी हाल की बरसात में हमने देखा है। मौसम का कोई सैट पैटर्न नहीं होता, एक जमाना था जब मौसम का सैट पैटर्न होता था और आने वाले सीजन के लिए हम पहले ही तैयारी करके रखते थे। लेकिन इस बार मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि उस हिसाब से तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हिमाचल प्रदेश में भी रेनी सीजन का दो-ढाई महीने का समय होता है लेकिन यहां पर वर्षा का रेगुलर डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता। कहीं ज्यादा बारिश हो गई, कहीं कम हो गई, कहीं सूखा पड़ गया और कहीं बादल फट गया तथा उसी अनुपात में नुकसान भी होता रहता है। हमें शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने पहली जून से 23 अगस्त तक के जिलावार आंकड़े दिए हैं कि कहां कितनी वर्षा हुई है। उससे पता चलता है कि चम्बा जिला में 49 प्रतिशत, किन्नौर में 42 प्रतिशत, लाहौल-स्पिति में 56 प्रतिशत और सिरमौर में 7 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। जबकि हमीरपुर जिला में 16 प्रतिशत, कांगड़ा में 20 प्रतिशत, कुल्लू में 17 प्रतिशत, शिमला में 17 प्रतिशत और ऊना में 33 प्रतिशत ज्यादा वर्षा हुई है। जहां पर वर्षा ज्यादा हुई है वहां ओब्वियसली नुकसान भी ज्यादा हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर राजस्व विभाग ने नुकसान के अनुसार कम्पनसेशन देना है तो उसके लिए हमारे मौसम विभाग ने अच्छे आंकड़े दिए है। वर्षा के कम-ज्यादा होने से मेसिव लैण्ड स्लाइड होते हैं जिससे भारी नुकसान होता है। किसी के घर के पीछे या आगे से अगर लैण्ड स्लाइड होता है और गरीब

है तथा उसका कच्चा घर गिर गया है तो उसको प्रोपर कम्पनसेशन मिलना चाहिए जिसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इस नुकसान की भरपाई के लिए 96 करोड़ रुपये की राशि दी है। अब देखना यह है कि वह राशि ग्राउंड स्तर पर कितनी जल्दी लग सकती है। यह बात सत्य है कि जहां जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो तब होगी जब राजस्व रिकार्ड के अनुसार उसका

24.8.2018/1430/AV-AG/2

सही ज़ायजा लिया जायेगा लेकिन एड्होक एड सबको मिली है और समय पर मिली है इसमें कोई शक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है और मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। मेरी जानकारी के अनुसार शायद 10-12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में आई0पी0एच0 का लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों का करीब 4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शुरू में हमारी लगभग 27 सड़कें बंद थीं लेकिन मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 27 सड़कों में से हमारी 25 सड़कें पहले दिन ही ट्रेफिक के लिए क्लीयर कर दी थी। हमारा प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर बार-बार लैण्ड स्लाइड होते रहते हैं मगर हम साथ-साथ अपना काम भी करते रहते हैं। इस बार प्रदेश में लगभग 25-26 जानें गई हैं और 11-12 की रात को ही 15-16 जानें गई हैं। उनको सरकार प्रोपर कम्पनसेशन दे रही है और इसमें कोई शक नहीं है। यह नुकसान हर वर्ष होता है और पिछले पांच वर्ष भी होता रहा है। लेकिन इसमें हम एड्होकिज्म फोलो करते हैं। हम पहले से उतनी तैयारी नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि इसकी सख्त जरुरत है कि हम अगली आने वाली बरसात से निपटने के लिए किस ढंग की तैयारी करें। हमारी जितनी भी कमेटियां हैं उनको किस तरह से तैयार करें। पिछले पांच साल में भी नुकसान हुआ है और आपने किस तरह का

कम्पनसेशन दिया है वह हम सबको पता है। इसीलिए क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान होता है लेकिन हम जमीन पर क्या कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण है।

श्री टी सी द्वारा जारी

24.08.2018/1435/TCV/DC/1

कर्नल इन्द्र सिंह ..... जारी

ये सरकार मेरे क्षेत्र में तो बहुत चिंतित रही है और जैसे ही किसी का नुकसान हुआ हमने उनको तुरन्त फौरी राहत देने का काम किया है। उन लोगों को समय पर यह राहत दी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1435/TCV/DC/2

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत यहां पर जो चर्चा हो रही है कि प्रदेश में वर्षा से भारी नुकसान हुआ है, उस पर सभी ने अपनी चिन्ता जाहिर की है। मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपकी घण्टी का इंतजार भी नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। हम पहले तो जो हमारे चश्में हैं, उनके नम्बर बदल दें। जब यहां पर इस प्रकार की चर्चा होती हो तो कोई भी राजनीतिक भावना से अपने विचार न रखें। क्योंकि जिन लोगों की मौतें हुई है, जो लोग तबाह हुए हैं और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हम उनके बारे में यहां पर माननीय मुख्य मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़े होते हैं।

अध्यक्षः किसी का मोबाइल बज रहा है। कृपया बन्द कर दें। इससे डिस्टरबेंस हो रही है।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लो किसी की जान चली जाये या किसी का पशु मर जाये तो उसको जो सहायता दी जाती है, उसको कम्पनसेशन नहीं बोला जाना चाहिए, उसको राहत राशि बोला जाना चाहिए। माननीय सदस्य कर्नल साहब जी कह रहे थे कि उस नुकसान का सही मुआवज़ा मिलना चाहिए। लेकिन जो भी मद्द हो रही है या सरकार मद्द कर रही है, उसके बारे में कईयों ने कहा कि बहुत अच्छी मद्द हो रही है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे प्रकरण को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। बरसात हुई है, यदि ये कहा जाये कि मौसम विभाग ने पहले कहा था कि इन-इन दिनों में ज्यादा बारिश होगी और सरकार को उसके बारे में सजग रहना चाहिए था। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग जिला स्तर पर भी होती रही है। लेकिन जब आपत्ति आती है तो वह इन्विटेशन देकर नहीं आती है। यहां पर यदि यह कहा जाये कि फलां जिला में इतनी बारिश हुई, इसलिए उसका ज्यादा नुकसान हो गया और फलां जिला में कम बारिश हुई, उसमें कम नुकसान हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर बादल फटा और जो नुकसान हुआ वह जिला की ज्यादा व कम बारिश से नहीं आंका जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां-जहां पर बादल फटे हैं, जहां-जहां पर भी इस

24.08.2018/1435/TCV/DC/3

प्रकार की त्रासदी हुई है, उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात अवश्य लाना चाहूंगा कि आपने अभी नये-नये पटवारी लगाये हैं। हमारे एरियाज़ में पटवारी भी मौके पर नहीं गया, राहत देने की बात तो अलग है। मेरे चुनाव क्षेत्र के धौलाधार में मछवारे का एक मकान गिरा और उसमें एक आदमी की मौत हो गई व दो आदमी घायल हो गये। जब मैं हास्पिटल में गया और वे लोग पोस्टमॉर्टम के लिए बॉडी लाये थे तो वहां पर काननूगो ने उनको मु0 10 हजार रुपये तुरन्त राहत राशि के रूप में

दिए। मेरे चुनाव क्षेत्र के दगशेच में एक हरिजन है, उसके दोनों बैल और पशुओं को बाधने के लिए जो कमरा बनाया हुआ था वह भी बह गया । वहां पर आज तक पटवारी नहीं पहुंचा है। मेरी अपनी पंचायत के साथ की वह पंचायत है। जब मुझे वह आदमी मिला जिसके पशु मर गये तो उन्होंने कहा कि पटवारी ने 4 दिन के बाद रिपोर्ट लिखी है। लेकिन उसको तुरन्त राहत राशि के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया है।

श्रीमती एन0एस0 ..... द्वारा जारी।

24-08-2018/1440/NS/DC/1

श्री राम लाल ठाकुर ....जारी

ऐसे ही सुख राम नाम का एक व्यक्ति मेरी अपनी पंचायत का है। उसके बैल मरे, उसके पास कोई नहीं गया। एक कृष्ण सिंह नाम का व्यक्ति शौरी पंचायत का और एक धूणी पंचायत का है, इनके मकान गिरे हुए हैं लेकिन इसके पास कोई भी अधिकारी नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसा न हो कि अधिकारियों को टेलीफोन चले जायें कि आप वहां पर चले जाओ, टेलीफोन न जाये तो आप वहां पर न जाओ। इसको बराबरी के आधार पर देखना चाहिए। त्रासदी तो त्रासदी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पानी की स्कीमें बह गई हैं, वह जल्दी से रीस्टोर होनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के परगना बहादुरपुर, परगना रत्नपुर, चंगर एरिया और स्वार घाट के एरिया में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि वहां से पानी आ रहा हो। सारी-की-सारी स्कीमें बंद पड़ी हुई हैं। मैं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी इन स्कीमों को रीस्टोर कर दिया जाये ताकि लोगों को सही तरीके से पानी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस प्रकार की परिस्थितियों में यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के मकान गिरे हुए हैं, वहां पर कल्याण विभाग के चेयरमैन हैं और कल्याण समिति की जिला में मीटिंग होती है तथा गरीबों के मकान बनाने के प्रस्ताव पंचायतों से आते हैं, उनको इसके लिए राहत राशि दी जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय

मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कृपा करके जिनके मकान गिर गये हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए यह आदेश दिये जायें कि इनके मकान प्राथमिकता के आधार पर बनाये जायें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंचायत का रेजोल्यूशन आना चाहिए और जनरल हाउस की मीटिंग में पास होना चाहिए, तब गरीब का घर बनाया जाएगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो आपकी कल्याण समिति है या जिले में ब्लॉकस से जो मकान बनते हैं या रिपेयर के लिए जो पैसा आता है जिन-जिन के मकान गिरे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पैसा मिलना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा से ले करके गोविंद सागर के किनारे की जो सड़कें हैं, एक भी सड़क ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। बड़ी सड़कों की रिपेयर तो हो जाती है। आज अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में जितने भी फलों और सब्जियों की पैदावार होती है, वह

24-08-2018/1440/NS/DC/2

अगर मान लो हमारे प्रदेश की सड़कें ठीक नहीं होंगी तो कुल्लू, लाहौल और स्पिति, मण्डी से जो बे-मौसमी सब्जियां/फल आ रहे हैं, इनकी सप्लाई कैसे होगी। हमारा एरिया नेशनल हाईवे में आता है। नेशनल हाईवे कीरतपुर से ले करके नोणी मोड़ तक है। वहां पर सड़क और खड्ड में कोई अन्तर नहीं है। जितने भी ट्रक जा रहे हैं, जितनी भी सब्जियां सप्लाई हो रही हैं या जितने भी फल मार्किट तक पहुंचेंगे अगर सड़क ही ठीक नहीं होगी तो कैसे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में फोरलेन बन रही है और इसका काम अढ़ाई साल से बंद पड़ा हुआ है। वहां से ठेकेदार भाग गये हैं। जो हमारा डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे ऑथोरिटी इसकी मरम्मत नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमैंट कह रही है कि यह नेशनल हाईवे ऑथोरिटी का काम है और हमारे जमींदारों का इससे नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग पांच खड्डें हैं। सीर खड्ड, शुक्र, सरियाली, गम्बर और गम्बरोला तथा अली खड्डें हैं और इन खड्डों में इतनी बाढ़ आई है कि लोगों की ज़मीनें, मकान और घराट भी बह गये हैं। लोगों का रोज़ी-रोटी कमाने का साधन खत्म हो गया है। मैं यहां पर नाज़ायज़ कब्जों की बात नहीं करूंगा। भारी बारिश के कारण लोगों की मलकियत ज़मीन बह गई है और घर भी बह गये हैं। कई लोगों के घराट और

गौशालायें बह गई हैं। इसके लिए मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि कृपा करके राहत राशि जल्दी से दी जाये और केंद्र सरकार से भी मदद के लिए निवेदन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा। हमारी जितनी भी सड़कें हैं, उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से टीम आएगी और यहां पर हुई क्षति को नोट करेगी तथा इसके बाद हम इन सड़कों को ठीक करेंगे। वहां पर थोड़े-थोड़े मलबे को हटाया जा रहा है ताकि गाड़ियां निकल जायें। अगले दिन फिर बारिश होती है और उतना ही मलबा वहां पर इक्ट्ठा हो रहा है और इस डेबरीज़ को उठाने में दिक्कत आ रही है। मेरा अनुरोध है कि आप इसके लिए केंद्र सरकार से निवेदन करें कि केंद्र से टीम समय पर आ जाये ताकि इन सड़कों की ठीक ढंग से इक्ट्ठी रिपेयर हो जाये। ऐसा न हो कि हमने डेबरीज़ के चार ट्रक उठाये और अगले दिन बारिश हुई तथा 10 ट्रक और आ गये, फिर सड़क बंद हो जाये। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।

अगला वक्ता-----श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

24.08.2018/1445/RKS/HK-1

अध्यक्षः अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, भारी बारिश के कारण जो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ, उस पर आपने नियम-130 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझ से पहले सभी वक्ताओं ने विस्तार से अपनी बात सदन में रखी। हम पहले नम्बर में भगवान को और दूसरे नम्बर में सरकार को मानते हैं। प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा आने पर सरकार लोगों की मदद करती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने सड़कों की मरम्मत के लिए राशि जारी की। सारी सड़कें चकाचक थीं परंतु 14 तारीख की भारी बारिश के कारण ये सड़कें खड्डों में तबदील हो गईं। हर जगह भू-स्खलन हुआ और सड़कों पर मलबा गिरा। लेकिन मैं लोक निर्माण विभाग का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने सारी सड़कों की मरम्मत कर दी। आज सभी सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। ठाकुर साहब कह रहे थे कि गांव में यातायात को बहाल करने के लिए अभी

तक JCB नहीं पहुंची है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके लिए संबंधित विभाग के लोग प्रयास कर रहे हैं। बारिश के कारण 50-60% डंगे गिर चुके हैं। मैंन दो-तीन जगह चार-पांच घर ऐसे देखे जो नीचे आने वाले हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के चंगर एरिया में कम-से-कम 15-20 घर और मवेशीखानें गिर गए हैं। पटवारियों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार लोगों को थोड़ा-बहुत मुआवजा भी मिला है। । दरिया के किनारे लोगों की मक्की की फसल बरबाद हो गई है। हम 'सनातन धर्म' को मानने वाले लोग हैं और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस दिन ब्यास नदी में इतना ज्यादा पानी आया कि 100 से ज्यादा आवारा बैल और गउएं उस पानी में बह गईं। कई जगह भैंसें, बकरियां मवेशीखानों के नीचे दब कर मर गईं। इसके अलावा कई स्कूल भवन भी गिरे हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा.... जारी

24.08.2018/1450/बी.एस/एच.के./-1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी...

पंचायतों द्वारा जितने पुल बनाए गए थे वे सारे-के-सारे पुल खड्डों के साथ बह गए हैं। किस स्थान पर कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता मुल्यांकन कर रहे हैं। मैं इस माननीय सदन में यह कहना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग में लगभग 6-7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और आई.पी.एच. विभाग में भी 5-6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही डेढ़-दो करोड़ रुपये का नुकसान लोगों के मकान गिरने से हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस आपदा से निपटने के लिए कोई-न-कोई नीति बनाई जाए। क्योंकि जिन लोगों के निजी डंगे घरों में लगे थे वे पूरी तरह से गिर चुके हैं। इस पर सरकार की नीति है कि निजी तौर पर डंगे लगाने के लिए कोई राहत नहीं दी जाती । मेरे क्षेत्र में मुझे मिलने के लिए वर्षा से प्रभावित 106 लोग आए थे और 106 में से 40 लोग ऐसे थे जिनके मकानों के डंगे गिर

चुके हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी-न-किसी योजना के तहत उन लोगों को राहत देने की कृपा करें, क्योंकि इन लोगों में से कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। यहां पर जैसा पूर्व में कहा गया कि मकान सबसे पहले गरीब लोगों को आबंटित किए जाएंगे। मेरा मानना है कि जो लोग टैंट लगाकर बाहर बैठे हैं उन्हें अवश्य सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए। आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने पड़ौसियों के घरों में शरण ले करके रह रहे हैं। यह जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें सरकार कुछ हद तक भरपाई भी कर रही है परंतु अभी और अधिक करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अवश्य इस बारे कोई नीति बनाई जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.08.2018/1450/बी.एस/एच.के./-2

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 130 के तहत जो आदरणीय अनिरूद्ध सिंह जी ने यहां प्रस्ताव लाया है उसमें बोलने के लिए मौका दिया आपका धन्यवाद। वैसे तो सारी बातें कही जा चुकी है क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो होती है यह किसी के बस की बात नहीं होती है। आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर नुकसान नहीं हुआ है। मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ दो-तीन चीजें अवश्य इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं। आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कहा कि किस जगह कितनी बारिश हुई है, परंतु मैं माननीय राम लाल ठाकुर जी की बात से सहमत हूं कि कहां ज्यादा बारिश हुई, प्रश्न यह नहीं है । परंतु नुकसान कहां ज्यादा हुआ यह अहम बात है। हो सकता है कई जिलों में औसतन बारिश कम हुई हो परंतु कई स्थानों पर बादल फटा और नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर मैं चम्बा जिला की बात करूं तो जिला चम्बा में भयंकर नुकसान हुआ है। चाहे आप चम्बा शहर को ले लें, ततवानी के पास पूरा डंगा चला गया है और शहर का रास्ता बंद पड़ा है। आदरणीय

जरयाल जी के क्षेत्र भटियात में अगर आज का समाचार पत्र पढ़े तो मेरे ख्याल से चलांवा में पूरी पंचायत ही वर्षा के कारण प्रभावित हो गई है। नेशनल हाइवे डलहौजी व चम्बा सारे का सारा क्षेत्र अलग हो गया। यह ठीक है कि जहां सम्भव हुआ लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को खोला है। मगर जो लगातार बादल फट रहे हैं उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जैसा कि ठाकुर राम लाल जी ने कहा कि एक दिन हम मलबा हटाते हैं दूसरे दिन उससे दोगुना मलबा वहां आ रहा है। मेरे और आदरणीय जरयाल साहब के चुनाव क्षेत्र की सीमा में दुनियारा नामक एक स्थान है, वहां पर इतना ज्यादा नेशनल हाइवे पर मलबा आया है और पूरा रास्त बाधित हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी उसी रास्ते से मिंजर मेले के बाद निकले थे ।

श्री डी.टी. द्वारा जारी

24.08.2018/1455/डी.टी./वाई.के./-1

श्रीमती आशा कुमारी जारी...

आप बहुत धुंध में यात्रा कर रहे थे, मैंने वहां आपको क्रोस किया था उसी स्पोट पर यह सारी स्थिति बनी हुई है। वहां पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। पर्यटन का जो पूरा कैफेटेरिया है, किसी को रेंट आउट किया है या शायद सेल हो गया है । उस कैफेटेरिया के अंदर तक पत्थर चले गए और जो लोग वहां बैठे हुए थे वे जख्मी हो गए। इतना ज्यादा नुकसान उन जगहों पर हुआ है। सभी माननीय सदस्य सरकार से उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास भी रखते हैं कि सरकार नुकसान की भरपाई करेगी । इस विषय पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। इस पर जो भी फंड्स दिए जाएंगे वह नुकसान के हिसाब से जारी करेंगे। किसी जिला या एरिया को राजनीति से प्रेरित हो कर न छोड़ दें। आपके पास इस बारे में कितने फंड्स आए हैं? आप इसका जरूर इस माननीय सदन में जिक्र करें। आपने कितना फंड्स केन्द्र सरकार से मांगा है इसका भी जिक्र आप करेंगे। मुझे लगता है कि 15 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभी बारिश बंद नहीं हुई है, अभी

अनुमान यह है कि 2-4 दिनों में भारी बारिश होगी। पता नही अभी और कितना नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। जहां तक हमारा अनुभव है आपका भी होगा, सभी का अनुभव है कि सितम्बर और अगस्त में जो बारिशों से नुकसान होता है वह बहुत ज्यादा होता है। अभी यहां बारिश से नुकसान हो रहा है । उसके बाद जब धूम निकलेगी उससे अलग नुकसान होगा। धूप लगने के बाद जब धरती पानी छोड़ेगी उस वक्त भी नुकसान ज्यादा होगा। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहती हूं कि यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ में नहीं है परंतु जो हम पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हैं, यह आपके और हमारे हाथ में है। इन परिस्थितियों से निपटले के लिए जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कोशिश की हैं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, परंतु वास्तव में हमारी योजना क्या है । अध्यक्ष महोदय जितना हम छेड़छाड़ करेंगे। उतना ही नुकसान हमें छेलना पड़ेगा। चम्बा जिला में और अन्य स्थानों पर जहां भी हाइड्रो इलैक्ट्रिक्स प्रोजैक्टस बने हैं। वह एक मेजर कारण है जो हमारे यहां छेड़-छाड़ हुई है यह मुख्य कारण माना जा सकता है। अध्यक्ष महोदय एक और चीज यहां पर में बताना चाहती हूं। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ हैं यह बाकी पहाड़ों की तुलना में

24.08.2018/1455/डी.टी./वाई.के./-2

मजबूत पहाड़ हैं। आपने भी बतौर अध्यक्ष पानी के स्रोतों के बारे में एक स्ट्डी करवाई है । विधान सभा की जो ई-ग्वर्नेंस कमेटी है उसमें आपने यह सब स्ट्डी किया है । जिस दिन इस विषय पर चर्चा हुई उस दिन माननीय अध्यक्ष महोदय आप उस बैठक में उपस्थित नहीं थे परंतु हमने इस विषय को स्ट्डी किया है। उसमें हमने देखा है कि जो हमारी पहाड़िया हैं उन पर हम लगातार बोझ डालते जा रहे हैं। अब निर्माण देखिए, अधांधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं। चाहे आप शहरी इलाके देख लीजिए, चाहे ग्रामीण इलाकों को देख लीजिए। अब शहरों में जमीन घटती जा रही है, इस कारण लोग ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहे हैं। शहरों के साथ लो इलाके हैं चाहे आप शिमला को ही देख लीजिए, शिमला में इतना बड़ा

नुकसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो शिमला में ही पली-बढ़ी हूं। खासकर जो पुराना शिमला है। हैनोल्ट स्कूल के ऊपर लैंड स्लाईड हुई, 16 देवदार के पेड़ के नीचे आ गए। प्रोपर्टी का नुकसान हुआ। ऐसा ही हाई कोर्ट के पास जहां से हम और आप रोज आते-जाते हैं उस रास्ते जल्दी खोला जाएगा ऐसा नहीं लगता। ये सारा बिल्डिंग का प्रैशर है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपको एक सुझाव देना चाहती हूं । ये जो बिल्डिंगस बन रही है, जो हमारा नोटिफाइड ऐरिया है चाहे वह कमेटी का ऐरिया है, कॉरपोरेशन का ऐरिया है जो टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग का एरिया है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी...

24/8/2018/1500/वाई0के0/एन0जी0-1

श्रीमती आशा कुमारी ..... जारी

(सभापति महोदय श्री नरेन्द्र बरागटा पदासीन हुए)

मगर लोग क्या कर रहे हैं? जहां टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग का ऐक्ट खत्म होता है उसके immediately बाहर 7-7 मंजिल बिल्डिंग्ज बनाई जा रही हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं, ये ठीक है कि जो ढाई स्टोरी भवन बनने हैं, वह चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो उसके उपर आप कोई रोक न लगायें । मगर जो कोई लोग होटल्स बना रहे हैं, अपार्टमैंटस बना रहे हैं, 7-7 मंजिलों के भवन बना रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। आप बनीखेत से डलहौजी चले जाईए, जितनी बिल्डिंग्ज डल्हौजी में नहीं बनी है उससे ज्यादा वहॉ बनी हैं और कोई भी बिल्डिंग 7 मंजिल से कम नहीं है । रूरल ऐरियाज में जो बिल्डिंग्ज बना रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखे। अगर किसी को Commercial building बनानी है तो उसके उपर कानून लागू होना चाहिए वरना ये जो हमारे पहाड़ हैं इनकी ecology खराब हो जाएगी

और पहाड़ वजन को सहन नहीं कर पायेंगे। धीरे-धीरे erosion बढ़ता जाएगा और इस erosion की वजह से हमारे जो शहर के आसपास के जितने इलाके हैं, आप कहीं भी चले जाईए, आप मण्डी चले जाईए, चम्बा चले जाईए, डल्हौजी चले जाईए जहॉ-जहॉ आपके बडे कस्बे हैं वहॉ आपको यही दिक्कतें आती जा रही है। ये मेरा आपको सुझाव है। इसके बारे में आप सोचिए। मुख्यमन्त्री महोदय मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि Commercial activities के लिए चाहे वह प्लानिंग का ऐरिया है, चाहे नहीं है, आप कुल्लु, मनाली में देख लीजिए जहॉ पर टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग का एरिया खत्म होता है उसके बाहर लोगों ने बड़ी- बड़ी बिल्डिंगे बना ली हैं। लोगों ने 7-7 मंजिलें बना ली हैं। डल्हौजी से चम्बा को एक सडक जाती है, खोलपुखर और कोलडी़ होकर, अगर

24/8/2018/1500/वाई0के0/एन0जी0-2

आप उस सडक पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुरे चम्बा जिले में इतनी बिल्डिंगज़ नहीं होंगी जितनी अकेली इस सडक पर हैं और ये थिक फोरेस्ट है। कमेटी एरिया जहां खत्म होता है उसके आगे बिल्डिंग्ज बन रही हैं। इस तरह की चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं तो ये डिजास्टर होते रहेंगे। हमको इससे सीख लेनी है। डिजास्टर मैनेजमैंट का मतलब यह है कि we should look for ways to stop this from happening. ये जो आप कर रहे है, ये तो आप करेंगे ही। आपके पास मशीनरी उपलब्ध है वो तो आप लगाएंगें ही। मशीनरी हमारी सरकार के समय भी आई और जहां कमी होगी आप भी लाएंगे । नैश्नल हाईवे पर मशीनरी है। जहां पर पानी की स्कीम्ज गई हैं उसके लिए भी आप पैसे देंगे । मगर हमेशा नुकसान सैंकड़ों -करोड में होता है और भरपाई के लिए पैसा बहुत कम आता है । मुख्यमन्त्री महोदय आपने भी केरल फल्ड के लिए सरकार की ओर से 5 करोड रू0 दिए । हमने भी अपनी तरफ से सहयोग दिया । मगर मेरा ये मानना है कि charity begins at home. वहां के लिए हम सबने दिया, अच्छा काम किया। मगर यहां के लिए भी करें तो और अच्छा होगा। केन्द्र सरकार से आप इस बात को

जरूर टेकअप करें, और जैसा की मुझ से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र की टीम को जल्दी आने के लिए प्रेरित करें । ऐसा ना हो कि हम उनके इन्तजार में न सडकें खोलें और बाद में वे न पैसे दे, ऐसा अक्सर होता है। आप जानते हैं कि आपदा होती है 1500 करोड की और पैसा आएगा केवल 200 करोड। ये आपको Prioritize करना पडेगा और मैं ध्वाला जी से सहमत हूॅ। इन्होंने बात कही कि जिनके घर गिरे हैं, उनके बारे में आप Deputy Commissioners को डेफिनेट instructions दे दिजिए, खासकर के जो लोग SC/ST में आते हैं, जिनको हम पैसा वैलफेयर से दे सकते हैं। उनको Top Priority में घर सैंक्शन कर दिए जाएं । रामलाल जी ने ठीक बात कही कि पटवारी मौके पर जा नहीं रहे और हम लोगों को भी अधिकारियों को फोन करने पड रहे हैं। चाहे Deputy Commissioner से बात करनी पड़े चाहे SDM से बात करनी पडे तब पटवारी मौके पर जाते हैं

24/8/2018/1500/वाई0के0/एन0जी0-3

लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । लागों को पैसा नहीं मिल रहा है, उनके घर गिर गए हैं। जिसका घर गिर गया है अगर उसको आप पांच हजार रूपये देंगे तो उसका क्या बनेगा? अगर वो SC/ST से हैं तो कम से कम उनको वैल्फेयर से immediately पैसे सैंक्शन कर दिए जाएं। ये उन लोगों के लिए एक भारी रिलीफ हो सकती है। सडकों के लिए आप करेंगे, हर जिले के लिए भी आप करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मुख्यमन्त्री जी आप seriously सोचेंगे कि हम बिल्डिंग्ज के प्रैशर को किस तरीके से घटा सकें? सभापति महोदय, आपका धन्यवाद ।

24/8/2018/1500/वाई0के0/एन0जी0-4

सभापति महोदयः माननीय सुखराम चौधरी जी

श्री सुख राम चौधरीः आदरणीय सभापति महोदय जी, नियम 130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव इस सदन में श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने रखा था, मैं उसके उपर बोलने के लिए खडा हुआ हूं।

प्रदेश में पिछले दिनों बहुत बरसात हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान इस बरसात से हुआ है । जिला सिरमौर में भी बहुत नुकसान इस बरसात के समय में हुआ है । दिनांक 26-07-2018 को गिरि नदी में अचानक बाढ आने से गोशालवाला पंचायत डोबरीशालवाला में 8 लोग और लगभग 50 पशु गिरि नदी के बीच में फंस गए ।

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

24/08/2018/1505/RG/AG/1
श्री सुख राम-----जारी

क्योंकि जब गिरी नदी का पानी **स**तौन से छोड़ा जाता है तो वह बहुत फोर्स के साथ नीचे आता है और एक-डेढ़ या दो घण्टे में वह नीचे पहुंच जाता है। जब तक लोग बाहर नहीं जाते हैं। मैं उसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि 26 तारीख को 5.15 बजे सूचना आई। देहरादून से तुरन्त एन.डी.आर.एफ. की टीम मंगवाई गई और रात को 11.30 बजे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जबकि वह अंधेरे का समय था और अगले दिन स्थानीय प्रशासन ने सारे पशु भी नदी से बाहर निकाल लिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विशेष रूप से पांवटा साहिब विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, (श्री नरेन्द्र बरागटा) जिला सिरमौर वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे यहां सड़कों की हालत भी दयनीय है और इस बरसात में पांवटा डिवीजन में, पांवटा विधान सभा क्षेत्र में बी. एण्ड आर. विभाग द्वारा 4,08,80,000/-रुपये के नुकसान का आकलन किया गया जो डी.सी. ऑफिस ने कनवे किया है। नाहन में 5,56,85,000/-रुपये, शिलाई में 9,54,26,000/-रुपये, संगडाह में 10,91,10,000/-रुपये और पच्छाद में 3,56,10,000/-रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आई.पी.एच. डिवीजन पांवटा में भी 11,49,70,000/-रुपये का नुकसान हमारे एक डिवीजन में इस बरसात के कारण हुआ

है। पच्छाद में शिलान्जी पंचायत है। वहां पशुशाला गिरने से 6 पशु दबकर मर गए। मैं स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहली मर्तबा जिला सिरमौर की सड़कें, तीन सड़कों को छोड़कर कोई भी सड़क 24 घण्टे से ज्यादा बंद नहीं हुई। प्रशासन मुस्तैद रहा। समय-समय पर सड़कें खुलती रहीं। केवल मात्र अभी तक दो सड़कें बंद हैं। एक टिम्बी से दभोट चार किलोमीटर की सड़क है जो पी.एम.जी.एस.वाई. से बनी है और शिलाई विधान सभा क्षेत्र की है। दूसरी सड़क नाहन-ददाहू-संगडाह-हरिपुरधार है जो संगडाह और हरिपुरधार में स्लिप आने के कारण एक रिटेनिंग वॉल डैमेज हो गई है। केवल छोटी गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, यूटीलिटी क्रॉस कर रही है लेकिन बड़ी गाड़ियां क्रॉस नहीं कर रही हैं। एक सड़क चाड़ना-बुआई-संगडाह, यह भी आज शाम तक खुल जाएगी। सरकार के आदेशानुसार प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। परन्तु जो सड़कें ब्लॉक के माध्यम से बनाई गई हैं उनमें से बहुत सी सड़कें आज भी बंद हैं। बहुत से स्थानों पर

24/08/2018/1505/RG/AG/2

जिला सिरमौर में क्योंकि टमाटर की खेती होती है और आजकल टमाटर व अन्य सब्जियों का सीजन चला हुआ है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांवों के लिंक रोड्ज हैं और ब्लॉक के माध्यम से बनाए गए हैं, उनको खोलने की विशेष व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अभी 16 तारीख को आठ करोड़ रुपये रिलीफ के रूप में जिला सिरमौर को दिया है। जहां तक मैनुअल की बात है, लोगों के घर गिरते हैं तो हम 40,000/-रुपये तक अधिकतर नुकसान की भरपाई करते हैं और अधिकतर 20% तक की करते हैं। लेकिन आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय आज के समय में यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस मैनुअल को बदलने की जरूरत है। हम कई बार इस सदन में चर्चा करते हैं किसी का घर डैमेज हो गया, उसको वेलफेयर से घर दिया जाए। हम वेलफेयर से उसको घर कैसे दे सकते हैं? वेलफेयर में कितने घर आते हैं? एक विधान सभा क्षेत्र को 7-8 घर मिलते हैं। हम एस.सी. या एस.टी. को कितने घर वेलफेयर से दे देंगे?

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2018/1510/MS/AG/1

श्री सुख राम जारी----

इसलिए मैनुअल में इस चीज का प्रावधान किया जाए कि यदि प्राकृतिक आपदा में किसी का घर गिर जाता है तो प्राकृतिक आपदा के तहत जो फण्ड मिलता है, उस फण्ड के माध्यम से ही उसका घर बनाने का प्रोविजन किया जाए। तभी हम उसको फौरन राहत दे सकते हैं नहीं तो उसको राहत नहीं मिलेगी। वह व्यक्ति एस0डी0एम0 ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा या वैल्फेयर में एप्लीकेशन दे देगा और चक्कर काटता रहेगा लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज के समय में मैनुअल को बदलने की आवश्यकता है ताकि हम लोगों को राहत दे सकें।

जहां तक घरों की बात है तो भारी वर्षा के कारण कई बार रिटेनिंग वॉल डैमेज हो जाती हैं और आज सरकार की जो नीति है उसके अनुसार हम रिटेनिंग वॉल के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि स्थानीय प्रशासन को इस तरह का आदेश दिया जाए कि उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो ताकि नुकसान का आंकलन हो। इसके अलावा जहां बहुत जरूरी है तो उसमें राजस्व विभाग को इन्वोल्व करके उस परिवार का जिसका घर नहीं गिरा है बल्कि रिटेनिंग वॉल गिरी है उसको मैनुअल के हिसाब से स्थानीय प्रशासन को इन्वोल्व करके रिटेनिंग वॉल के भी पैसे देने की भी व्यवस्था, मैं चाहता हूं कि होनी चाहिए नहीं तो यह समस्या इसी तरह से खड़ी रहेगी। जब अभी पीछे काफी बरसात पड़ी उस समय बिजली की सप्लाई में भी बहुत बिघ्न पड़ा। मैं कहता हूं कि जिला सिरमौर में कम-से-कम 200 से 250 खम्भे टूट गए और कम-से-कम 50 नये ट्रांसफॉर्मर्ज लाइटनिंग की वजह से डैमेज हो गए। उनको बदलने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मौसम खराब है इसलिए अगर दूसरे ट्रांसफॉर्मर से बिजली लेंगे तो वह ट्रांसफॉर्मर भी ओवरलोड हो जाएगा और जल जाएगा। इसलिए बरसात के सीजन से पहले सही तरह की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए ताकि तुरन्त इस तरह की व्यवस्था करके उनको रिस्टोर करने का इंतजाम किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी दिनों से बिजली का व्यवधान पड़ रहा है। मैंने आदरणीय मंत्री जी से

24/08/2018/1510/MS/AG/2

भी कई बार निवेदन किया कि हमारे यहां पर 132 के0वी0 की सिंगल लाइन है और वह कई बार डैमेज हो जाती है या बन्द हो जाती है तथा उससे हमारे दो विधान सभा क्षेत्र पावंटा और शिलाई अंधेरे में चले जाते हैं। वहां बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है। पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के मित्रों ने पावंटा में बड़ा प्रदर्शन किया कि लाइट नहीं आ रही है। यह प्राकृतिक आपदा है और पूरा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर हम सब लोग मिलकर लोगों को रिलीफ देना चाहता हैं तो जो डैमेज बरसात में होता है, उसका अलग से मैनुअल बनाया जाए और पीड़ितों को तुरन्त राहत देने की व्यवस्था अलग से की जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

24/08/2018/1510/MS/AG/3

सभापति(श्री नरेन्द्र बरागटा): अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी: सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत जो सदन में चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

प्राकृतिक आपदाएं हर वर्ष आती रहेंगी और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परन्तु मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हमें पता था कि आपदाओं ने आना है तो उसकी हमने क्या तैयारी की है? दूसरा, जो आपदाएं आई हैं उसके बाद हमने राहत का काम कितने युद्धस्तर पर किया, यह दूसरा प्रश्न है। जहां तक पहले प्रश्न की बात है तो आपकी सरकार को बने हुए तकरीबन आठ महीने का समय हो गया है। आपने बड़ी-बड़ी बातें कीं कि हम बरसात और सूखे से निपटने के लिए तैयार हैं परन्तु इन आठ महीनों के अंदर ही जो बरसात या सूखा पड़ा, उसमें ही आपकी तैयारियों की पोल खुल गई है। सबसे पहले तो

शिमला शहर की बात करूंगा जहां पर इतिहास में पहली बार हुआ कि यहां पर पीने-के-पानी की इतनी किल्लत रही। वाशिगटन पोस्ट अखबार में भी खबर छपी कि कोई शिमला न जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि शिमला न आएं क्योंकि यहां पानी नहीं है। तो इतनी बड़ी असफलता आपके समय में हुई है। -(व्यवधान)-

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

24.08.2018/1515/जेके/डीसी/1

श्री जगत सिंह नेगीः----------जारी----------

आपकी तैयारी जो आपदाओं से निपटने पर है। यह जो बरसात की तैयारी थी , डिजास्टर मैनेजमैंट आपका बहुत बड़ा महकमा है, जिसमें आप सैमिनार पर करोड़ों रूपया खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रूपया आप डिजास्टर मैनेजमैंट की मीटिंग्ज पर खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रूपया आप डैमोन्स्ट्रेशन पर खर्च कर रहे हैं। कभी आप रिज मैदान में डैमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, कभी स्कूलों में दे रहे हैं और कभी सचिवालय में दे रहे हैं। इस तरह से करोड़ों रूपया डिजास्टर मैनेजमैंट पर खर्च हो रहा है परन्तु मौके पर जब भी कोई डिजास्टर होता है, चाहे छोटा सा एक्सिडैंट भी होता है तो ये जो डिजास्टर मैनेजमैंट कमेटी के अधिकारी हैं या जिन लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है, ये लोग कभी समय पर नहीं पहुंचते । अभी मैं आपको कल रात की घटना बताता हूं। राष्ट्रीय उच्च-मार्ग-5 जो कि यहां से कोरिक तक, चाइना बॉर्डर तक जाता है, वहां पर रात के 12.00 बजे एक ट्राला फंसने से पूरी की पूरी सड़क बन्द रही। ऑर्मी की कॉनवॉई बन्द रही और टोटल यातायात बन्द रहा। वहां पर 10 किलोमीटर पर एस0डी0एम0 का ऑफिस है परन्तु मेरे फोन करने तक एस0डी0एम0 को पता ही नहीं कि 12.00

बजे से सुबह तक नेशनल हाई-वे बन्द पड़ा हुआ है। कई सौ गाड़ियां दोनों तरफ से बाधित रही। यह हाल डिजास्टर मैनेजमैंट का है। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता है। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय, करोड़ों रूपए डिजास्टर में खर्च करने के बजाय इस डिजास्टर मैनेजमैंट को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। रात के 12.00 बजे, 2.00 बजे आप डिजास्टर

24.08.2018/1515/जेके/डीसी/2

मैनेजमैंट के लिए अफसरों को फोन करते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। अभी भारी बरसात में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। बहुत सारे लोग पानी में बह गए। सड़कें बन्द हुई लेकिन जो आपका तंत्र था वह पूरे का पूरा बन्द था। जब तक हमने उनको सूचना नहीं दी,कोई वहां से हिला नहीं। मैं अपने जिला किन्नौर की यदि बात करूं तो हमने रात के एक-एक बजे तक बैठ कर दो बड़े-बड़े पुलों को जो बिल्कुल ध्वस्त होने थे, उनको बचाया। उसमें हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमैंट के कुछ एक्सिअन, कुछ हमारे मैकेनिकल के जे0ई, मैं यहां पर उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, भीम सेन नेगी जी जिन्होंने रात के एक-एक बजे तक बैठ कर नेशनल हाई वे के पुल या रिब्बा गांव के पुल को बचाया है। उनको तो वाकई ईनाम देने की जरूरत है। बाकी जिला प्रशासन तो सोया रहा। न डी0सी0 मौके पर आता है, न एस0डी0एम0 मौके पर आता है जिनके पास डिजास्टर के सारे पॉवर्ज हैं। जिनके पास डिजास्टर की सारी धनराशि है। जब तक ये लोग जागृत नहीं होंगे तो हम डिजास्टर मैनेजमैंट का काम नहीं कर सकते। यह बात मैं आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि हमने तो Quick Reaction Team अपने जिला में भी खड़ी की थी। उसमें हमने ट्रेंड होम गार्ड भी रखे। उनको इक्विपमैंट्स भी दिए लेकिन पिछले 8 महीने में वह Quick

Reaction Team ही गुम हो गई। लाखों रूपए की गाड़ी का हमने प्रबन्ध किया जिसके अन्दर सारे साजो-सामान थे। वह अब चलता ही नहीं है।

दूसरी बात राहत देने की है। अभी केरल में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। 21 हजार करोड़ रूपए की बात उन्होंने की है और केन्द्र सरकार ने मात्र 500 करोड़ रूपए दिए। अभी आपने पता नहीं कितने करोड़ रूपए का यहां से केस भेजा है ? अगर आप 500 करोड़ रूपए का केस भेजेंगे तो उस अनुपात में तो आपको पांच लाख भी नहीं मिलने वाला है। तो किस तरह से आप डिजास्टर मैनेजमैंट के अंतर्गत हमें राहत देने वाले हैं? अभी वहां से मेरे कुछ साथी कह

24.08.2018/1515/जेके/डीसी/3

रहे थे कि इनके चुनाव क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन वे दबी जुबान में कह रहे थे। शायद मुख्य मंत्री जी को खुश करने की बात होगी। ये कह रहे हैं कि उनके यहां बहुत अच्छे राहत के काम हुए परन्तु गांव में जा कर पूछिए जिसका मकान आज गिरा है उसको आपने कहां अभी राहत दी है? बरागटा जी यहां से आप खुद कह रहे थे, अब तो आप सभापति जी वहां पर बैठे है, मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा।....(घंटी).... अभी तो पांच ही मिनट हुए । आठ मिनट तो आपने कम से कम समय रखा है। इतने गम्भीर मामले में आप समय नहीं दे रहे हैं। पांच मिनट में घंटी बजाने का तो मतलब ही नहीं है। अभी आप खुद कह रहे थे कि हाटकोटी रोड़ में सारे का सारा गड़बड़ हो गया। आज शिमला जिला में सेब का निष्कासन बहुत मुश्किल हो गया है। आज शिमला जिला की सारी सड़कें टूटी हुई है । उसके ऊपर आप बोलना तो चाह रहे थे लेकिन आप दबी जुबान में बोले। बोले तो सही परन्तु आप देखिए कि कहां आपका सेब निकल रहा है? आज छोटी गाड़ियों का रेट जहां पर 500/-रूपए

देना था वहां पर 1000/-रूपए ले रहे हैं। इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है और मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि जो असली मुद्दा है, उससे आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं। साथ में बिजली बोर्ड, आई0पी0एच0 का भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। जो रिलीफ में पहले आपने थोड़ा-बहुत पैसा दिया हुआ है वह जिला स्तर पर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइ0पी0एच0 विभाग वाले डी0सी0 को पत्र लिखते हैं, पी0डब्ल्यू0डी0 वाले डी0सी0 को पत्र लिखते हैं कि हमारी इतनी सड़कें डैमेज हुई है हमें रिलीफ में पैसा दिया जाए परन्तु उसमें एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तर पर आप एक रिलीफ कमेटी गठित करें ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2018/1520/SS-DC/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागतः

उसका चेयरमैन चाहे आप मंत्री जी को रखें या डी0सी0 को रखें परन्तु सारे विधायकों को उस रिलीफ कमेटी का मेम्बर बनाया जाए। उसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को मेम्बर बनाया जाए ताकि जो रिलीफ का पैसा आता है उसके ऊपर डिस्कशन हो और उसको बांटने का एक सार्थक तरीका अपनाया जाए, वह बहुत ज़रूरी है। जब तक वह नहीं करेंगे तो इसकी बंदरबांट होगी। जब डी0सी0 के पास एप्लीकेशन जाती है तो जिस पंचायत का प्रतिनिधि ठीक है या किसी मंत्री का फोन आ जाता है तो सारा पैसा एक तरफ को डाईवर्ट हो जाता है।

सभापतिः नेगी जी, कृपया वाइंड अप करिये।

श्री जगत सिंह नेगीः सभापति महोदय, पहले आप घड़ी देखिये।

सभापतिः मैंने घड़ी देख ली है।

श्री जगत सिंह नेगीः आपने मेरे दो मिनट खराब कर दिए हैं। अभी सात मिनट लगे हैं। You cannot interrupt me like this.

सभापतिः मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप बोलिये।

श्री जगत सिंह नेगीः आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं बोलना ही बंद कर देता हूं। --(व्यवधान)-- आप टाइम देख लीजिए।

सभापतिः आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं सब को पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री जगत सिंह नेगीः आप मुझे किस नियम के तहत रोक रहे हैं? You quote the Rule.

सभापतिः पांच मिनट सब को दे रहे हैं। आप मुझे धमका रहे हैं। आप मुझे धमकाने का काम मत करो। सब को पांच मिनट दे रहे हैं और आपको पांच मिनट से सात मिनट हो गए हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः पांच से सात मिनट होने दो। आठ मिनट तक टाइम एलो किया है।

सभापतिः आप वाइंड अप करिये।

24.08.2018/1520/SS-DC/2

श्री जगत सिंह नेगीः आपने 11 और 12 मिनट तक भी टाइम दिया है। आप स्वयं 12 मिनट बोले हैं।

सभापतिः आप गुस्सा क्यों कर रहे हो?

Shri Jagat Singh Negi: This is not the way. आप मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते।

सभापतिः आपकी आवाज को कौन दबा रहा है?

श्री जगत सिंह नेगीः आप मेरी आवाज को दबा रहे हो। आपने पांच-छः बार घंटी कैसे बजा दी? रूल्ज़ में कहां लिखा है कि पांच मिनट में घंटी बजेगी?

सभापतिः सभी को पांच मिनट दे रहे हैं, कोई आपके लिए अलग से रूल थोड़े बनना है। We are giving five minutes to everybody. You cannot be subject to that?

श्री जगत सिंह नेगीः यह सदन मिल-जुलकर चलेगा। You are not the Master of the House, you are the servant of the House.

सभापतिः यह गुस्सा आप कहीं और जाकर निकालो।

श्री जगत सिंह नेगीः यह गुस्सा नहीं है। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मुझे भी लोगों ने यहां चुनकर भेजा है। ---(Interruption)--- How can he interrupt me.

सभापतिः पांच मिनट सब को दे रहे हैं और आप सात मिनट ले चुके हैं। --(व्यवधान)-- मुकेश जी, इनका इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। Just a minute. मैंने इनको इंट्रप्ट नहीं किया। मैंने बोला कि आप वाइंड अप करिये। I have not interrupted you. जब पांच मिनट में समाप्त करना है तो क्या यहां पर सारी रात ही लगे रहेंगे? सबने पांच-पांच मिनट लिये हैं। माननीय आशा जी ने भी पांच मिनट लिए हैं। सब पांच-पांच मिनट ले रहे हैं। अब तीन मिनट आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं। माननीय मुकेश जी, आप बोलिये।

24.08.2018/1520/SS-DC/3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यु है और प्रदेश में जो नुकसान हुआ है हमने पहले ही कहा कि हम इस इश्यु को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ट्राईबल इलाके से आते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उस तरफ ही होता है। आप उनकी पूरी बात सुनें, अभी पांच बजे तक बहुत टाइम है। --(व्यवधान)-- अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाते हैं। अगर बरसात में हुए नुकसान के इश्यु पर भी आप हमें पूरा टाइम नहीं देते और रूलिंग पार्टी के मेम्बर्ज़ का ऐसा बिहेवियर है तो हम चले जाते हैं। हम इस हाउस में किसलिए आए हैं? --(व्यवधान)-- धक्काशाही नहीं चलेगी।

सभापतिः मुकेश जी, मेरी बात सुनिये। I am asking him to speak.---(Interruption)---.

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हमने पहले ही कह दिया कि यह राजनीतिक मसला नहीं है हम आपके साथ हैं। बरसात में नुकसान हुआ है उसमें मदद की जायेगी।

सभापतिः मुकेश जी, सुनिये तो सही I We are asking him to continue but he cannot continue for hours. माननीय आशा जी, सबसे वरिष्ठ हैं she has taken only five minutes. मैं पांच मिनट सब के लिए बोल रहा हूं। एक-दो मिनट आगे बढ़ जायेंगे तो ठीक है लेकिन ये ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। नेगी जी, आप बोलिये। आपको बोलने से कौन रोकता है लेकिन आप पांच मिनट के बजाय दस मिनट नहीं ले सकते। You cannot take others share.

श्री जगत सिंह नेगीः मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरा बोलने का तरीका यही है।

सभापतिः तरीका तो मेरा भी ऐसा ही है।

24.08.2018/1520/SS-DC/4

श्री जगत सिंह नेगीः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात और रखना चाहता हूं। अभी हमारे साथियों ने भी इसकी चर्चा की है। जो कैलामिटी रिलीफ फंड है उसमें जो पैमाना रखा गया है जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कों का है, आई0पी0एच0 की स्कीमों का है और जैसे प्राईमरी और मिडल स्कूल तक ही आपने सीमित रखा है उसमें पैसा बहुत कम है। किलोमीटर के हिसाब से रिलीफ में जो पैसा रखा है उस हिसाब से हमारी सड़कें खुल नहीं सकती हैं। इस ओर भी आपको ध्यान देना है। कैलामिटी रिलीफ फंड में विशेष करके आई0पी0एच0 और पी0डब्ल्यू0डी0 का पैसा बढ़ाना है।

दूसरी बात यह है कि जो लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं, अभी मेरा विधान सभा में एक प्रश्न था कि जनजातीय क्षेत्रों में एस0सी0/एस0टी0 के कितने मकान पिछले तीन सालों से लम्बित हैं तो उसके जवाब में बताया कि कोई

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2018/1525/केएस/ऐचके/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

साढ़े तेरह हजार से ज्यादा लोग आज भी इन्तज़ार में हैं कि उनके मकान वैल्फेयर के माध्यम से बने। वैल्फेयर के माध्यम से जिन लागों के बाढ़ से मकान खराब हुए हैं, उनको तो देने का यहां पर प्रश्न ही नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री सुख राम जी ने सुझाव रखा है कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में अगर लोगों के मकान ध्वस्त होते हैं, उनके लिए अलग से फंड रखा जाए, यह बिल्कुल सही है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ कि बादल फटने व बाढ़ आने से खासकर हमारे जिला किन्नौर में हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर जो पुल को नुकसान हुआ है, रिब्बा गांव में पुल का नुकसान हुआ है, होल्डो नाला में पुल का नुकसान हुआ है, सीरिंग में और बोनिंगसारिंग में नुकसान हुआ है, कटगांव में और उसके साथ सुरचो और अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है, जहां आज भी पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं है। कटगांव के पूरे गांव में पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। हमने बार-बार सरकार के ध्यान में लाया कि रिलीफ फंड में से इस रास्ते को बनाने के लिए पैसा दिया जाए लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और हमें जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर राहत प्रदान करेंगें। धन्यवाद।

सभापतिः शाबाश । ऐसे ही प्यार से बोला करो, अच्छा लगता है but you have took ten minutes. The mover of this Resolution was asked to speak for ten minutes and you have taken eleven minutes. अगर ऐसे प्यार से बात करोगे तो बात हो सकती है परन्तु गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए।

अब माननीय राकेश जम्वाल जी।

24.08.2018/1525/केएस/ ऐचके /2

श्री राकेश कुमारः माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हाल ही में बारिश के कारण जो नुकसान हुआ, नियम-130 के तहत आपने मुझे भी उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वह हम सभी के सामने है । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों का जिक्र किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस बारिश के मौसम में काफी नुकसान हुआ है। काफी सड़कें टूट गई, पीने के पानी की स्कीमें खराब हो गई। बिजली का नुकसान हुआ लेकिन मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बारिश से मेरे चुनाव क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, आपके आदेशानुसार शत-प्रतिशत बिजली और पानी की सप्लाई बहाल हुई है । हमारे अनेकों मित्रों ने यहां पर कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और यह पूछकर नहीं आती। हमारे उस तरफ बैठे सहयोगियों ने कहा कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि ऐसे समय में ऐसी आपदा से निपटने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की आपदा बताकर नहीं आती। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हमारी तैयारी नहीं थी, इसके लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी । आप केरल में देखें, केरल में क्या हुआ? सरकार किस प्रकार से वहां पर तैयारी करती है? हजारों लोग वहां पर बाढ़ के कारण मर गए लेकिन फिर भी आज पूरा देश केरल की जनता के साथ खड़ा है । इसी प्रकार अगर हिमाचल प्रदेश में भी नुकसान हुआ है तो हम सभी लोगों को मिल कर काम करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि हमारे वहां पर कोई कर्मचारी नहीं जा रहा है, अधिकारी नहीं जा रहे हैं, हमें ही फोन करने पड़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हम भी उस क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर हमने किसी अधिकारी या कर्मचारी को फोन कर दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसी घड़ी में हम सभी मिलकर प्रयास करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार से नुकसान हुआ,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

24.8.2018/1530/AV-AG/1

श्री राकेश कुमार-------- क्रमागत

हमारे जिलाधीश और एस0डी0एम0 ने वहां के सभी कर्मचारियों और पटवारियों को छुट्टी पर से वापिस बुलाया और सबको आदेश दिया। वहां पर जहां-जहां भी बड़ा नुकसान हुआ मैं भी उसका जायजा लेने के लिए उनके साथ गया। आदरणीय सुख राम जी ने ठीक कहा कि रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन होना चाहिए। हम सब लोग और विपक्ष में बैठे सीनियर लोग भी जानते हैं कि रिलीफ मैनुअल में पार्शली और फुली डेमेज के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है। हम सब लोग इस बारे में चिन्ता करें ताकि इसमें परिवर्तन किया जा सके और इस नुकसान के कारण जो लोग आहत हुए हैं उनके नुकसान की भरपाई हो। आदरणीय राम लाल जी ने भी ठीक कहा कि आज कीर्तपुर-मनाली एक सड़क नहीं बल्कि खड्ड बन गई है। हम भी वर्षों से चण्डीगढ़ और दिल्ली के लिए उसी सड़क से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उस सड़क की हालत पिछले 6 महीनों में ऐसी नहीं हुई है बल्कि पिछले कई वर्षों से उस सड़क की यही हालत है। आपने यह भी कहा कि चश्मे बदलने चाहिए। (---व्यवधान---) आपने जहां तक चश्मे बदलने की बात कही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां बैठे मेरे साथियों ने तो चश्मे बदले हैं लेकिन आप अपने सहयोगियों को भी अपने चश्मे बदलने को कहें। (---व्यवधान---) कीर्तपुर-मनाली फोर लेन सड़क का काम वर्ष 2013 से चला हुआ है। उस सड़क पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जलोड़ से लेकर के सुन्दरनगर तक पिछले समय में दुर्घटना में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। मगर उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया, यह उस समय की सरकार की गलती थी जो वहां पर विभिन्न दुर्घटनाओं में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी घड़ी में अगर हम इस

प्रकार के विचार प्रकट करेंगे तो मुझे लगता है कि यह बहुत दुःखद होगा। मैं समझता हूं कि इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है और पूरे प्रदेश के लिए इस विपदा से निपटने हेतु आदेश दिए हैं। इन्होंने यह नहीं देखा कि कहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है

24.8.2018/1530/AV-AG/2

या कहां पर बी0जे0पी0 के लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है यानि पार्टी के लोगों को ज्यादा सहायता दी जाए और कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं दी जाए। मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश में एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य नेगी जी अभी कह रहे थे और मुझे लगता है कि कहीं पर किसी घटना के घटने से पहले ही उनको पूर्वाभास हो जाता है। भविष्य के लिए हम मान्यवर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि उनसे जरूर सलाह ले लिया करें कि कहां पर क्या नुकसान होने वाला है ताकि समय रहते सम्भला जा सके। आपको शायद सांगला के बारे में ध्यान नहीं होगा कि वहां पर क्या आपदा आई थी। यहां पर बैठे मेरे साथियों ने अच्छा कन्ट्रिब्यूट किया है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बरसात में जो प्रदेश में नुकसान हुआ है उससे निपटने के लिए सभी सहयोग करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार आज पूरे प्रदेश में एक समान विकास कर रही है और इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। पूरे प्रदेश की सड़कें खोल दी गई है, मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल हाई-वे बंद था। सुबह पांच बजे मुझे किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी बस सुबह चंडीगढ़ जा रही है। चंडीगढ़ से हमारी विदेश के लिए 12 बजे की फ्लाइट है लेकिन सड़क वहां पर अवरुद्ध है। मैंने तुरन्त लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा और उन्होंने आधे घंटे के अंदर उस सड़क को खोला तथा वहां से ट्रैफिक थ्रू किया जिसके कारण उनकी विदेश यात्रा सफल हुई। मैं ज्यादा न बोलता हुआ यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विकट

परिस्थिति में जिस त्वरित तरीके से इस प्रदेश में बरसात के कारण हुए नुकसान से निपटने का प्रयास किया है उसके लिए मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद

24.8.2018/1530/AV-AG/3

सभापति (श्री नरेन्द्र बरागटा) : अब माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल : मानीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर यह सदन विचार करे, यह जो प्रस्ताव लाया गया है इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बरसात और बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर चर्चा की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्लेन एरिया में किस तरह की बाढ़ आती है वह आपने केरल में देखा।

श्री टी सी द्वारा जारी

24.08.2018/1535/TCV/YK/1

श्री नन्द लाल जी ..... जारी

लेकिन हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र में टॉपोग्राफी इस तरह की है कि ज़रा सी बारिश होने से कई ऐसे छोटे-छोटे नाले जहां पानी होता ही नहीं है, वे आजकल बरसात के दिनों में नदी का रूप धारण किए हुए हैं। जहां तक सड़कों की बात है, सड़कों में जो टारिंग-मैटलिंग और वाइडनिंग का काम चल रहा है, उसमें जो रिटेनिंग वॉल जहां-जहां पर लगी है, उसके गिरने का बड़ा खतरा रहता है। इसलिए सड़कें अवरूद्ध हो रही है। इसके अलावा ऊपर से कटिंग करने से जो मलबा पड़ता है, उससे भी सड़कें अवरूद्ध होती हैं। सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। हम इसको मानने से मना नहीं कर रहे हैं। हम यह

कहना चाहते हैं कि जब शेड्यूल होता है, बरसात के मौसम से पहले या सर्दी के मौसम से पहले तो जिला स्तर पर एक मीटिंग होती है और डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार किया जाता है। उसमें हमारी कमियां नहीं रहनी चाहिए। अभी कुछ दिनों तक कई जगह सड़कें अवरूद्ध रही और कई दो-चार दिन बाद खुली। यहां तक कि नेशनल हाईवे भी बन्द रहा। जहां तक स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की बात है, उस पर तो जैसे-तैसे काम चल रहा है। लेकिन जो सड़कें ब्लॉक के माध्यम से बनी है, वह भी सरकारी फण्ड से बनी हैं। ये सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। लेकिन जो सड़कें सरकारी फण्ड से बनी है, उनका भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि हिल एरिया में जो सड़कें ब्लॉक के थ्रू बनी है, ये सड़कें एम0एल0ए0 फण्ड, एम0पी0 फण्ड या लोगों ने अपने पैसे इक्ट्ठे करके बनाई हैं। वे लगभग सभी बगीचों या खेतों में जा रही है। उनकी हालत अच्छी नहीं हैं। लोक निर्माण विभाग का जवाब रहता है कि ये सड़कें हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। After all it is a welfare state. इससे सेब की आर्थिकी पर भी फ़र्क पड़ रहा है। काशापाट का जो रोड हैं, वह लगभग तैयार था और आप लोग कह रहे थे कि एक-दो महीने में बन जाएगा। लोगों ने सेब के लिए बहुत तैयारियां कर रखी थी। लेकिन आज वे लोग बहुत परेशान है। उसमें काम बिल्कुल बन्द है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसमें थोड़ा-सा काम रह गया है,

24.08.2018/1535/TCV/YK/2

उसको करवा दिया जाये। ताकि उन लोग आने वाले समय में इस प्रकार की त्रासदी से न जूझना पड़े । इस बार जो नुकसान होना था, वह तो हो चुका है।

दूसरा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टिक्कर-खमाड़ी रोड है वह ननखड़ी गांव के बीच से जाता है जोकि एक सेब का एरिया है। उसकी हालत खराब है। उसकी कुछ रिपेयर इत्यादि करनी थी लेकिन उसमें पैसों की कमी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि उस सड़क के लिए फण्ड का प्रावधान करने की कृपा करें ताकि इसकी रिपेयर इत्यादि

की जा सके। क्योंकि ये रोड आजकल बुरी तरह से खराब हुआ है। इसमें से बड़ी-बड़ी लोडिड गाड़ियां निकालने में बहुत मुश्किल हो रही है और बसों के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि उस पर भी काम तेज़ किया जाये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसी तरह से पानी की भी कई स्कीमें अवरूद्ध हुई है। माननीय सिंचाई एव जन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे इस ओर ध्यान दें। मेरे चुनाव क्षेत्र की एक पूरी पंचायत आज भी पानी की समस्या से जूझ रही है। पहले वहां पर ड्रॉट पड़ा और अब जब पानी पर्याप्त मात्र में है तो उनके पास पाइप्स नहीं हैं और न ही उनके पास फण्डज हैं। हमने उनको कहा कि है इसका एस्टिमेट बनायें और हम इसके बारे में सरकार से बात करेंगे। घलैडा-मज्योटी पंचायत में आज भी तीसरे या चौथे दिन पानी आ रहा है। जबकि पूरे प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि उसके लिए जो पाइप्स परचेज़ करने या फण्डज की जरूरत है, उसको जल्दी-से-जल्दी उपलब्ध करवाया जाये ताकि उस स्कीम को चालू किया जा सके और वहां के लोगों को इस त्रासदी से निजात दिलाई जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सभी ने कहा कि हमें बारिश से हुए नुकसान को भारत सरकार से टेकअप क1रना चाहिए। यह जरूरी है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार से टेकअप किया जाये। लेकिन इसमें देरी न हो। ऐसा न हो की उनकी टीम आए, इंसपैक्ट करें और उसके बाद इसका निदान सोचे। इसमें देर हो जाएगी।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ..... जारी ।

24-08-2018/1540/NS/YK/1

श्री नन्द लाल ....जारी

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो जगह बादल फटे हैं। बादल फटने से दो जगह इतना नुकसान हुआ कि उस नाले में जितने भी लकड़ी के पुल और जो दूसरे पुल थे, वे सारे पुल बह गये हैं

तथा लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि इन पुलों को जल्दी बनाया जाये। 15-20 के कूट और क्यावग पंचायत के जो 3-4 गांव हैं, ये बहुत बुरी हालत में हैं, सारे रास्ते टूटे हुए हैं, उनको भी ठीक किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तकलेच पंचायत में भी बादल फटे हैं। वहां पर अनार के बाग में बाढ़ आ गई है और वहां पर मिट्टी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है। एक आदमी की गौशाला गिर गई है और उसके सारे पशु मर गये हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है और जो उन्होंने राहत राशि देनी होती है, वह देते हैं। यहां पर सब माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि रिलीफ मैनुअल को चेंज किया जाए। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए राहत राशि का अलग से पैकेज़ होना चाहिए। इस राशि को डिज़ास्टर मेनेज़मैंट में रखा जाए। इसका कान्टिजैंसी प्लान में इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जल्दी से रिपेयर की जा सके। अगर गौशालायें नहीं बनायेंगे तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि अभी जहां-जहां भी ये बादल फटे हैं और लोगों के घरों व खेतों की जो क्षति हुई है, इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने राहत राशि तो दे दी है लेकिन इनका दोबार से सर्वे किया जाये और समाधान किया जाये ताकि लोगों का और नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24-08-2018/1540/NS/YK/2

अध्यक्षः श्री मुकेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज हमारी युवा कांग्रेस का प्रोटैस्ट अम्बेदकर चौक पर हो रहा था और शांतिपूर्वक प्रर्दशन पर जिस ढंग से पुलिस ने डंडे बरसाये हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार शांतिप्रिय प्रदर्शन पर गोली-डंडा चलाने पर आ जाएगी तो लोकतंत्र की मूल भावनायें समाप्त हो जाएंगी। आप अपनी पुलिस को डंडे के प्रयोग के लिए नियंत्रित रखें। अभी शुरूआती दौर है और अगर आप इस तरह से डंडे चलायेंगे तो वे भी यूथ के लोग हैं, बच्चे हैं। उन्होंने प्रोग्राम दे रखा है कि आज हमने विधान सभा का घेराव करना है। इसमें हम सब विधायक भी गये थे और उनसे मिल करके आये हैं तथा इसके

बावजूद कि यह सदन चले, हम सब विधायक यहां पर मौजूद हैं। यह बहुत गलत बात है कि युवाओं पर डंडे चलाये गये हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हमारे नौज़वान घायल हुए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किन तौर-तरीकों पर सरकार आ गई है? मुख्य मंत्री जी इसके बारे में जो भी कहें लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। जिस ढंग से युवाओं पर झूठे केस बनाने का प्रयास हो रहा है, यह बिल्कुल अनुचित है। हमने सुबह भी कहा था कि प्रदर्शनकारियों पर डंडे न चलाये जायें लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। वहां पर 1500-2000 प्रदर्शनकारी आराम से बैठे हैं। आप इनकी तस्वीरें देख लें। बैठे हुए लोगों पर इस ढंग से डंडे चला देना और प्रोवोक कर देना कोई सही बात नहीं है।

24-08-2018/1540/NS/YK/3

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यूथ कांग्रेस की ओर से एक प्रदर्शन का आयोजन विधान सभा घेराव की दृष्टि से हमारी जानकारी में पहले से था। स्वाभाविक रूप से, लोकतंत्र में यह सारा क्रम चलता रहता है। एक निर्धारित स्थान पर उनकी गैदरिंग अलौ हुई और प्रमुख नेता यहां से जा करके उनको संबोधित करके आये। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह तो शुरूआती दौर है। ऐसी परिस्थिति ही अभी तक प्रदेश में नहीं है और किन वज़ह से सीसिल होटल के सामने से वे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते-करते यहां तक आये। बेरिकेड्स लगे थे और उन बेरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश हुई।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

24.08.2018/1545/RKS/AG-1

मुख्य मंत्री... जारी

मुझे लगता है कि नारेबाजी का कोई विरोध नहीं करता है। नारेबाजी होती रहती है। पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से उनको रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्मित करने की क्या आवश्यकता पड़ी कि जिन डंडो पर झंडे लगाए थे, उन डंडों को उन्होंने पुलिस के ऊपर फैंक दिया? आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? पुलिस के ऊपर पथराव

किया गया जिसमें ए.एस.पी. सहित तीन पुलिस कर्मचारी घायल हुए। यह शुरूआत कहां से हुई?

(कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

मुझे लगता है कि आप बहुत हलकी बातों में यह सब कर रहे हैं जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके नियंत्रण में ऐसी चीजें नहीं है तो आप कह दीजिए। हमने 15-15, 20-20 हजार जनसमूह के कई बार प्रदर्शन किए हैं। लेकिन यहां पर कुल 500 लड़के थे और प्रदर्शन को जिस तरह से उग्र रूप दिया गया उसकी मंशा को हम अच्छी तरह समझते हैं। यह मुझे बहुत बुरा लगा और इस तरह के प्रदर्शन नहीं करने चाहिए। इस तरह आप बड़े नहीं हो सकते हैं। ...(व्यवधान...) आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान...) अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ...(व्यवधान...) किस ने शुरूआत की, किसने पत्थर फैंके, किसने लाठियां फैंकी इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। आखिरकार विधान सभा सत्र चला हुआ है और ऐसी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की जिम्मेवारी है। ...(व्यवधान...) आने वाले समय में सैकड़ों प्रदर्शन होंगे लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रदर्शनकारियों को समझा कर आइए। ...(व्यवधान...)

24.08.2018/1545/RKS/AG-2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री और सत्तापक्ष के लोग पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। पुलिस ने जानबूझकर हमारे लोगों को मारा है। ...(व्यवधान...) वहां पर कोई बैरिकेडस नहीं थी।

(सत्तापक्ष और कांग्रेस विधायक दल के लोगों की आपस में काफी नौकझौंक हुई।)

संसदीय कार्य मंत्रीः आपका प्रोटैस्ट दर्ज़ हो गया है। ...(व्यवधान...)

श्री बी0एस0 द्वारा.... जारी

24.08.2018/1550/बी.एस/ए.जी./-1

(व्यवधान).....

(सभी कांग्रेस विधायक अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे-बाजी करने लगे।)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : सरकार ने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वे लोगों पर मन-मर्जी से डण्डे बरसा रही है। उन पर जांच करने की बजाए सरकार उन्हें क्लीन चिट दे रही है। ....(व्यवधान).....

(विपक्ष के सभी सदस्य नारे लगाते हुए बहिर्गमन कर गए।)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर विषय को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। सुबह जिस विषय को ले करके विपक्ष के साथियों ने यहां पर नियम 67 के अन्तर्गत नोटिस दिया था, यदि सचमुच में इन सारे विषयों को ले करके ये गम्भीर होते तो यह परिस्थिति यहां पर उत्पन्न नहीं होती। मुझे पिछले कल से ही इनकी नीति के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त हो रही थी कि इनकी संख्या बड़ी नहीं होगी । परंतु कुछ कांग्रेस के नेता चाह रहे थे कि खबर बड़ी बननी चाहिए। इसके बाद बात यह भी आई कि उन्हें पुलिस के साथ उलझना है और उलझन ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस को लाठी-चार्ज करना पड़े। इस नीति के तहत अखबार में खबर बड़ी बनेगी। यह सारे-का-सारा कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमने भी विधान सभा के बाहर प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन मात्र 500 की संख्या में नहीं किए हैं बल्कि 20-20 हजार की संख्या में किए हैं। मुझे अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना था, वे यहां से चले गए हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि एक प्रदर्शन कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विधान सभा के बाहर हुआ था और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये लोग सत्ता में थे उसी दिन कांग्रेस

ने सत्ता के बल पर अपनी ओर से भी प्रदर्शन कर दिया। हमारे लोगों के ऊपर पथराव किया गया। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शांता कुमार जी के हाथ में पत्थर लगा, चोट इतनी ज्यादा थी कि उनके हाथ में टांगे तक लगे थे। मैं मानता हूं कि यह परम्परा अच्छी नहीं है न ही इसके परिणाम अच्छे होते हैं। मैं कभी भी ऐसी बातों का समर्थन नहीं करता। आज भी अध्यक्ष महोदय, भाषण-बाजी के बाद कांग्रेस का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था।

24.08.2018/1550/बी.एस/ए.जी./-2

खबर यह भी है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब हम चले जाते हैं उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उन्हें यह कह कर आ गए कि आपको जो करना है आप कीजिए। उन्हें Instigate करके आ गए। उसके बाद सब लोग अंदर नहीं आए बल्कि कुछ लोग वहां पर उपस्थित रहे। जो लोग वहां पर थे वे बाद में विधान सभा के गेट के पास जो बेरिकेडस लगे थे वहां पहुंच गए। विधान सभा का सत्र चल रहा है इसलिए यहां पर पुलिस ने कानूनी तौर पर व्यवस्था बनाई । इन्हीं कारणों से पुलिस ने उन्हें गेट के बाहर रोका कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। वे लोग धरने पर बैठे रहे, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए, पुलिस ने कुछ नहीं कहा । जब वे बेरिकेडस के ऊपर चढ़ गए तो भी पुलिस ने उन्हें समझाया कि आप यहां मत चढ़िए। फिर भी ये लोग नहीं माने इन्होंने जो पार्टी के झण्डे हाथों में ले रखे थे उनमें लगे डण्डो को पुलिस के ऊपर फैंकना शुरू कर दिया। जिससे पुलिस के लोग भी घायल हो गए हैं। इतना होने के बावजूद पुलिस क्या करती?

श्री डी.टी. द्वारा जारी ....

24.8.2018/1555/डीसी/डीटी/1

मुख्य मंत्री द्वारा जारी.....

पीछे से पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया गया। ए.एस.पी. सहित कई पुलिस कर्मियों को घायल किया गया। मुझे अभी सही संख्या मालूम नहीं है। घायलों को अस्पताल ले गए। पुलिस वालों ने बल का प्रयोग नहीं किया वहां पर वाटर कैनन इस्तेमाल की गई। ऐसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था को मैंनटेन करना लाजमी था। मुझे लग रहा है कि इनके नियंत्रण में बहुत सारी चींजें नहीं है और इसका प्रदर्शन आपने पूरे प्रदेश में देखा होगा। एक नेता दूसरे के खिलाफ बोलता है और यही परिस्थिति यहां पर है। जो यहां पर आज घटना हुई इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मेरे साथी लोग बाहर चले गए। राजनीति में इतने जल्दी लाभ लेने की बातें मत सोचो। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनको यह मान कर चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में मजबूत है और इसे पांच वर्ष तक कोई नहीं हिला सकता। आप मुद्दों को उठाइए। यह बात हमें समझ में आती है। लेकिन सारे कानून की धज्जियां उड़ा कर इस प्रकार से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि वह भाषा भी गलत और तरीका भी गलत है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको जाना चाहिए और नौजवानों को ठीक प्रकार से गाइड करना चाहिए। आपका जो प्रदर्शन का मकसद था वह पूरा हो गया। आपने अपनी बात रख दी। आपका खबर लगाने का मकसद पूरा हो गया। आप शांतिप्रिय ढंग से आगे भी कहते रहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज की घटना सचमुच में दुर्भाग्य पूर्ण है जिसकी मैं निंदा करता हूं।

24.8.2018/1555/डीसी/डीटी/2

अध्यक्षः जो नियम 130 के ऊपर चर्चा चल रही है यदि सदन के नेता और अन्य सभी का एकमत हो तो अभी इसमें 13 लोग भाग ले चुके हैं और बोलेने वालों की बड़ी संख्या है और विषय वही है। अगर हम सीधा माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब इस समय लें और माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति हो तो जो नियम 130 के अंतर्गत चर्चा चल रही है 'प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान की भरपाई पर यह सदन विचार करे' का उत्तर दें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा हुई। इस चर्चा में श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री हर्षवर्धन जी, श्री नरेन्द्र बरागटा जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री और श्री बलबीर सिंह जी की ओर से यह प्रस्ताव था। बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य अपनी विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का विषय रखना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय मैं इस बात से सहमत हूं कि यह प्रस्ताव लगभग मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा में आता है। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सत्र के दौरान भी हम इस बात को मानकर चल रहे थे कि इस विषय पर चर्चा भी आ सकती है इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव भी आ सकता है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

24/8/2018/1600/डी0सी0/एन0जी0-1

मुख्यमन्त्री..... जारी

मुझे लगता है कि स्वभाविक रूप से जब प्रदेश को बहुत बडी हानि होती है, त्रासदी की तरह नुकसान होता है तो ऐसे विषयों पर हम सब को सारी बातों से उपर उठकर के और सत्ता पक्ष-विपक्ष के लोगों को अपने-अपने विचार सांझे करने चाहिए और उसके साथ-साथ में हम किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के इस नुकसान के भरपाई के लिए अपना आगे का रास्ता निकाल सकते है उस पर सभी को अपने सुझाव भी देने चाहिए ।

मैं धन्यवाद करता हूं सदन के माननीय सदस्यों का कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में भाग लिया और चर्चा में भाग लेते हुए सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए है और अपनी विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को भी उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था कि खासतौर से विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहुत ही सहज तरीके से, शालीन तरीके से अपनी बात कही है, सिवाय एक सदस्य के । जो हमारे ट्राईबल के विधायक हैं श्री जगत सिंह नेगी जी की बात को लेकर के मैं बडा हैरान भी था कि "सरकार की तैयारी नहीं थी" और वो सारी बात को लेकर के ऐसे कह रहे थे कि जैसे आज से पहले हिमाचल प्रदेश में जो बरसात के दौरान जो त्रासदियां हुई है, बडे-बडे नुकसान हुए है, उन नुकसानों के दौरान उनकी सरकार में जो सभी बातें हुई उसमें उनकी बहुत बडी तैयारियां थी ।

अध्यक्ष महोदय, स्वभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमको ये मान कर के चलना चाहिए कि ऐसी बातों में हमें राजनिती का लाभ तलाशने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने इस विषय पर करने की कोशिश की और इस सन्दर्भ में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं।

हिमाचल प्रदेश की तैयारी की दृष्टि से श्री मुकेश अग्निहोत्री जी पूछ रहे थे कि आपने बरसात से निपटने के लिए बैठक कब की तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस वर्ष 4 जून, 2018 को हमारी पहली बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव (राज्स्व) की अध्यक्षता में विभाग की

24/8/2018/1600/डी0सी0/एन0जी0-2

बैठक करके तैयारी की शुरूआत हुई और सभी Deputy Commissioners को बरसात के खतरे के लिए आगाह कर दिया गया । हम इस बात से पहले से अवगत थे कि विपक्ष के लोग शोर डालने की कोशिश करेंगे, नुकसान हो चाहे ना हो लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति निकालने की कोशिश जरूर करेंगे । जब शिमला में पानी का संकट आया तो हम विपक्ष से सहयोग की उम्मीद कर थे और उनसे सहयोग नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला और मैं उन सभी बातों में जाना नहीं चाह रहा हूं । लेकिन उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर इनकी सरकार की बात कहें तो तब बरसात के मौसम को लेकर तैयारियों के सन्दर्भ में बरसात से पहले बैठक

हुई थी कि नहीं हुई थी परन्तु जानकरी मिली की तब जुलाई में बैठक थी, जब बरसात शुरू हो गई थी और इस वर्ष हम बरसात के शुरू होने से पहले ही इस बात की तैयारियों के लिए बैठ गए थे । लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में इस बात को मान कर चलना पडेगा कि बरसात से निपटना सम्भव नहीं है क्योंकि यह सब प्राकृतिक है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है । ये कोई मानवीय घटना नहीं इस बात को हमें स्वीकार करना पडेगा और जब बरसात समय से पहले शुरू हो गई और

श्री आर0जी0 द्वारा जारी.....

24/08/2018/1605/RG/HK/1

मुख्य मंत्री-----जारी

मौसम विभाग के अनुसार अभी हमें लग रहा था कि बरसात इतनी जल्दी शुरू नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद 27 जून से बरसात आरम्भ हो गई और 12 एवं 13 अगस्त को बहुत अधिक बारिश हुई। जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले एक दौर था जब सभी जगह लगभग सामान्य रूप से बारिश होती थी और सब जगह लगभग बराबर ही बारिश होती थी। लेकिन पिछले कुछ अर्से से कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं तो सूखे जैसी स्थिति है और कहीं पर बहुत अधिक बारिश होती है। अपने प्रदेश में ही कुछ जगह बारिश इतनी ज्यादा हो रही है जिससे पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगर हम 12 एवं 13 अगस्त की बारिश का जिक्र करें तो शिमला में जो बारिश रिकॉर्ड की गई, वह वर्ष 1901 के बाद 12 एवं 13 अगस्त को 24 घण्टे में ऐसी बारिश हुई है जिसके कारण प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। यह 24 घण्टे की बारिश सामान्य से लगभग 500% अधिक थी। अगर इस प्रकार हम पूरे प्रदेश की बात करें तो वर्ष 2011 के बाद पूरे प्रदेश में 24 घण्टे में अगर सबसे मूसलाधार बारिश हुई, तो वह अभी 12 एवं 13 अगस्त को हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को लेकर मुझे दुःख है कि जिस 24 घण्टे की 12 एवं 13 तारीख की बारिश का हम जिक्र कर रहे हैं उससे जानमाल का भी बहुत नुकसान हुआ है। इससे प्रदेश में 16 लोगों की जानें गईं। वैसे मैं इसका जिलावार ब्योरा यहां दे सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत समय लगेगा। यहां हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि बहुत सारे लोग मर गए। मैं मानता हूं कि जान तो एक भी बहुत होती है और जिसकी जान जाती है, उसके परिवार वालों को कितनी पीड़ा होती है, इस बात की हम अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में अभी तक भारी बरसात के कारण जान का जो नुकसान हुआ है, वह कुल 35 बनता है। ये हमारे ऊपर बहुत बातें कह रहे थे कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है। उनको यह मालूम होना चाहिए कि जब एक साल पहले जो कोटरूपी की घटना हुई थी जिसमें एक ही घटना में लगभग 40 लोग मर गए थे। मैं कहता हूं कि आप राजनीति करो, लेकिन कम-से-कम लाशों पर तो मत करो। अभी विपक्ष के लोग सदन से चले गए। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने व्यवहार किया, मुझे वे सब बातें उनकी बहुत बुरी लगीं।

24/08/2018/1605/RG/HK/2

अध्यक्ष महोदय, अगर हम प्रदेश में नुकसान की बात करें, अगर हम सड़कों एवं पुलों की बात करें तो इसमें लगभग 643 करोड़ रुपये के नुकसान का अभी तक आकलन किया जा चुका है। प्रदेश की 3916 पेयजल योजनाएं एवं 941 सिंचाई की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं और कुछ काफी अधिक प्रभावित हुई हैं। खासतौर से आई.पी.एच. विभाग का जो नुकसान है, यदि हम इन सारी योजनाओं का जिक्र करें तो लगभग 214 करोड़ रुपये का नुकसान बनता है। इसके साथ-साथ बिजली विभाग में भी नुकसान हुआ है, कई जगह पोल एवं ट्रांसफार्मर्ज गिर गए और कई स्थानों पर लैण्ड स्लाइड के कारण पूरे-पूरे स्पेन निकल गए हैं। इस प्रकार से विद्युत विभाग में लगभग 24.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अगर हम कृषि उपज के हिसाब से बात करें तो कृषि को लगभग 63.12 करोड़ रुपये के नुकसान का असैसमेंट किया गया है। इसी प्रकार कृषि योग्य भूमि को मुवलिक 11.57 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम इससे भी आगे बढ़कर बात करें तो

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2018/1610/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी----------

अभी तक वर्षा से प्रदेश को 990.54 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन है। यानी लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान पूरे प्रदेश को अभी तक हो गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे यहां पर इन्होंने 90 और 95 करोड़ रुपये का जिक्र किया। हमने 96.05 करोड़ रुपये जारी किया और वह तो हमने एक चीज का बीच में जिक्र किया लेकिन कुल-मिलाकर हमने अभी तक आपदा राहत कोष के अंतर्गत 230 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों को जारी कर दिया है। पता नहीं विपक्ष के लोग पूरी बात सुनते हैं या आधी बात सुनते हैं और फिर उन आंकड़ों पर उलझ जाते हैं। फिर जो उनको सूट करता है उसका जिक्र करते रहते हैं। मैं सुबह भी देख रहा था जब ये कानून-व्यवस्था पर सारी व्यवस्था को उठा करके बोलने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भी बहुत सारी बातें और आंकड़ें जो हकीकत नहीं हैं, उन आंकड़ों का ये जिक्र कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह विधान सभा एक ऐसा माध्यम है जहां पर जो आंकड़े हैं वे कम-से-कम सही बोलने चाहिए।

अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को हम अपने प्रवास से शिमला पहुंचे और उससे पहले ही चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सारे आकलन और आगे की सारी योजना कि आगे किस तरह से हमने सारी चीजों को स्ट्रेंथन/मैनेज करना है, उन सारी बातों को लेकर के बैठक हो गई थी लेकिन उसके बावजूद शिमला पहुंचने पर मुझे लगा कि हमें एक बैठक कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने निवास पर सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें

हमारी सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विस्तार से चर्चा होने के पश्चात जो चीजें करनी हमें आवश्यक लगी, उन सारी चीजों पर हमने काम करने के आदेश दिए।

जहां तक पूरे प्रदेश की सभी सड़कों की बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में लगभग 923 सड़कें वर्षा से प्रभावित हुई थीं। जिनको हम कह सकें कि कुछ सड़कें/रास्ते अवरूद्ध हुए, उनकी संख्या सिर्फ 51 है और उनको रिस्टोर करने की कोशिश लोक निर्माण विभाग की ओर से लगातार चली हुई है। जो मशीनरी विभाग के पास है उस मशीनरी का उपयोग वे प्रभावित स्थानों पर कर ही रहे हैं

24/08/2018/1610/MS/AG/2

लेकिन उसके अतिरिक्त हमने यह भी कहा कि सड़कें बन्द नहीं रहनी चाहिए क्योंकि एक तरफ हमारा सेब का सीजन भी शुरू हो गया है। इसके अलावा यदि सड़कें बन्द हो जाती हैं या यातायात प्रभावित होता है तो कई बार किसी मरीज को यदि अस्पताल पहुंचाना है तो उसमें भी कठिनाई होती है। उस दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं कि जितनी जल्दी सड़कें रिस्टोर हो सकती हैं, करें ताकि सुचारू रूप से यातायात चलता रहे। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य चीजों को लेकर भी हमने पूरे प्रदेश में प्रयत्न किए हैं। केन्द्र से हमने फिलहाल अभी अंतरिम राहत के तौर पर तुरन्त 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए निवेदन किया है। हम बहुत जल्दी ही 28 तारीख को दिल्ली में एक बैठक में जाने वाले हैं और स्वाभाविक रूप से उस मुख्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। वहां पर सभी मुख्य मंत्री अपने-अपने प्रदेश की सारी बात कहेंगे। सब साथियों की ओर से जैसे आग्रह आ रहा था कि केन्द्र से आग्रह करें कि वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केन्द्र से टीम समय पर आ जाए ताकि आकलन समय पर हो जाए और उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को केन्द्र से राहत मिल सके। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा कि केन्द्र से जल्दी-से-जल्दी टीम यहां आकर नुकसान का आकलन करे और जल्दी-से- जल्दी हमें मदद मिले।

मैंने मशीनरी का जिक्र कर दिया है कि सारी मशीनरी जो लोक निर्माण विभाग के पास है, वह मशीनरी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए हमने लगाई हुई है। इसके साथ-साथ हमने जो एक बात कही, जिसका खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह यह है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों के मकान चले गए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

24.08.2018/1615/जेके/वाईके/1

मुख्य मंत्रीः-------जारी--------

वह सचमुच बहुत पीड़ादायक है क्योंकि जिसका आशियाना टूट जाता है, घर चला जाता है उससे बड़ी क्षति कोई और नहीं होती है। उस नुकसान के लिए हमने डी0सीज़0 को आदेश दिए हैं और वह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है कि एक तो राहत समय पर पहुंच पाए, उस बात को सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ अगर अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, ओ0बी0सी0 से हैं, ट्राइबल से हैं, उनको वेल्फेयर कमेटी के माध्यम से एक प्रावधान रहता है कि हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत उनको प्राथमिकता के आधार पर मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जो इसके अंतर्गत नहीं भी आते, जिसका घर टोटल डैमेज़ हो गया प्राथमिकता के आधार पर उनको अलग से मकान देने का प्रावधान हो, इसको भी हम सुनिश्चित करेंगें ताकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाढ़ के नुकसान के कारण बिना घर के न रहे और उसको ऐसा जीवन न झेलना पड़े। एक बात और आई है जो हमारे लिए सचमुच बड़ा विषय बना है। नुकसान होता है, सड़क का नुकसान होता है तो हम लोक निर्माण विभाग को कहते हैं कि आप उसको रिस्टोर कर दो, डंगा लगा दो लेकिन जब किसी के घर के आगे या पीछे डंगा लगाने की बात आती है, अगर

वह डंगा लग जाए तो वह घर बच सकता है लेकिन अगर वह डंगा नहीं लगता है तो उस घर को बचाना कठिन हो जाता है और यह हमारे लिए एक चुनौती है क्योंकि यह प्रावधान के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। हम विचार जरूर कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका रास्ता निकल सकता है? उसके लिए हम आने वाले समय में विचार करेंगें कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है? लेकिन फिलहाल मनरेगा के अंतर्गत जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार वहां पर उस डंगे को

24.08.2018/1615/जेके/वाईके/2

तुरंत लगाने का प्रावधान किया जा सकता है। डिप्टी कमिशनर को हम इस बात के लिए आदेश दे देंगें कि जहां पर भी इस प्रकार होता है, सारा काम छोड़ कर कोई गली या सड़क टूटी है, उसका काम चार दिन बाद या एक हफ्ता बाद हो सकता है लेकिन किसी घर के आगे या पीछे डंगा टूट गया है और घर बिल्कुल कठिनाई में आ गया है और उसके गिरने की परिस्थिति बन गई है तो वह निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी इसके लिए जो भी सम्भव हो सकता है, हम करेंगें। हमारे मित्रों ने एक बात और कही कि आप जो राहत राशि दे रहे हैं, इसका आधार यह नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस का विधायक है या बी0जे0पी0 का विधायक है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि नुकसान, नुकसान है और नुकसान कहीं भी होगा, उसके हिसाब से सभी जगह मदद की जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें क्यों आ रही है? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति से हटकर बात कह रहे हैं लेकिन जब हटकर कहने की बात आती है तो कह ही देते हैं। यह आपको सोचना भी नहीं चाहिए कहना तो दूर की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे टूरिस्ट डैस्टिनेशन्ज़ हैं, खासतौर पर शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला आदि बहुत से स्थान हैं, वहां के लिए

डिप्टी कमिशनर्ज़ के साथ हमने सारे मामले को टेकअप किया है कि इन दिनों में कुछ ऐसे प्वाइंट्स ,जहां बरसात के मौसम में लगातार मलबा गिरने, पहाड़ गिरने, चट्टाने गिरने की बहुत ज्यादा सम्भावनाएं होती हैं, वहां इस बात को मौनिटर करें। स्थानीय लोगों को काफी जानकारी होती है कि ये-ये प्वाइंट्स हर बार बरसात के मौसम में खराब होते हैं लेकिन जो बाहर का आदमी आता है उसको जानकारी नहीं होती। वह रात या दिन में जब निकलता है, जानकारी के अभाव में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उस प्वाइंट से जब वे निकलते हैं तो वहां पर दुर्घटना होने की, नुकसान होने की आशंका रहती है। हमने कहा है कि ऐहतियात के तौर पर पुलिस विभाग भी उसमें सहयोग करें और डिस्ट्रिक्ट

24.08.2018/1615/जेके/वाईके/3

एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां इस प्रकार के प्वाइंट्स हैं, वहां ठीक तरीके से ट्रैफिक को रैगुलेट करें, ट्रैफिक को मोनिटर करें और लोगों को जानकारी दें कि यह प्वाइंट खतरनाक है, यहां से सावधानी के साथ आपको चलना है। अगर वहां से नहीं जा सकते तो उनको रोकना है क्योंकि न पहुंचने से बेहतर तो रुकना होता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

24.08.2018/1620/SS-YK/1

मुख्य मंत्री क्रगागतः

ऐसी परिस्थिति में हमने एक बात यह भी ज़रूर कही है।

उसके बाद यहां पर कालका-शिमला रोड की बात हुई। मैं इस बात से सहमत हूं कि कालका-शिमला रोड पर फोरलेन के लिए कटिंग का काम चला है। इसी तरह से कुल्लू-मनाली में फोरलेन के लिए कटिंग का काम चला है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक

परिस्थिति को मध्यनज़र रखते हुए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम पहाड़ को काटते हैं, मिट्टी के सैटल्ड स्ट्रैटा को काटते हैं तो उसमें बरसात के मौसम में इरोजन का बहुत बड़ा स्कोप रहता ही है। इस बात को हमारे इंजीनियर्ज़ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब एक बार कटिंग होती है तो उसको सैटल होने में तीन-चार साल लगते हैं। उस दृष्टि से जहां कटिंग हो रही है वहां पर ऐसी परिस्थिति आई कि शिमला-कालका मार्ग थोड़ी देर के लिए अवरूद्ध हुआ था लेकिन उसके बावजूद हमने उसकी एक लेन लगातार चलाए रखी है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सड़क सुचारू रूप से चले। ट्रैफिक को कंट्रोल/रैगुलेट करने के लिए हमने पुलिस के अधिकारियों को आदेश किये हैं कि वहां पर पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाए। उसके साथ-साथ जो मलबा ऊपर से आ रहा है उसको हटाने के लिए मशीनरी वहां स्पॉट पर उपलब्ध रहनी चाहिए। नियरैस्ट प्वाइंट पर मशीनरी उपलब्ध रहनी चाहिए। इस बात को भी हमने सुनिश्चित किया है चाहे वह कुल्लू की बात है, धर्मशाला की बात है या चाहे हमारे शिमला की बात है। इन बातों को हमने करने की कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस बात को मानकर चलना चाहिए कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिनमें काम करने में बाधा आती है। आखिर काम करने वाले भी इंसान ही हैं, जिन्होंने सड़कों पर अपनी जान को जोखिम में डाल कर मलबा हटाने के लिए मशीन से काम करना है। वह परिस्थिति भी हमको देखनी पड़ती है। इन सारी बातों को लेकर सरकार गम्भीर है।

यहां पर शिमला के बारे में बात कही गई कि शिमला का रास्ता दो-तीन प्वाइंटस पर अवरूद्ध पड़ा है। यहां हाई कोर्ट के पास रास्ता बंद हुआ है। मैंने कहा कि इतने दिनों से रास्ता बंद पड़ा है, अभी यह एक हफ्ते या दस दिन पहले की बात है। रास्ता दस दिन से बंद पड़ा है हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन इनको (विपक्ष) यह भी मालूम होना चाहिए कि पिछला एक दौर ऐसा भी रहा था कि जब वह सड़क तीन-चार महीने नहीं बल्कि एक साल तक रिस्टोर नहीं हो पाई थी। हम उन चीज़ों में जाना नहीं चाहते।

24.08.2018/1620/SS-YK/2

लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि सड़कों को जल्दी से रिस्टोर किया जाए। उसके साथ नुकसान की भरपाई को जल्दी से सुनिश्चित किया जाए। इसके

अतिरिक्त यातायात की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इस बात को भी सुनिश्चित करना है। मैंने कहा कि बरसात और सेब का सीज़न दोनों एक साथ होते हैं इसलिए हमारी प्राथमिकता यह निश्चित रूप से है। हम विभाग और सरकार की ओर से कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी को ज्यादा कठिनाई न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से प्रयत्न करने के लिए विभाग को बधाई देता हूं। विभाग बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा कि छोटी सड़कें कुछ जगह बंद होंगी लेकिन जो हमारे मेज़र डिस्ट्रिक्ट रोडस हैं उनके बंद होने की संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं था कि वे सड़कें बंद नहीं हुईं। सड़कें बंद हुई थीं लेकिन उनको तुरन्त रिस्टोर कर दिया गया। तुरन्त वहां मशीनें लगा करके सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया। तो हम आने वाले समय में भी तैयारी की दृष्टि से पूरी तरह से सतर्क हैं और कोशिश यही करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बावजूद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी हो सके और जो जान-माल का नुकसान हुआ है, जिनको राहत पहुंचानी है वह राहत उन तक पहुंचे। उसके साथ-साथ ऐसी परिस्थिति में जो केन्द्र से मदद आनी चाहिए, उसके लिए हम दिल्ली (केन्द्र सरकार) से जल्दी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी-से-जल्दी वह राहत यहां पहुंच सके और लोगों की हम उस राहत के माध्यम से मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण विषय आपने नियम-130 के अन्तर्गत इस माननीय सदन में चर्चा हेतु स्वीकृत किया है, मेरे इस उत्तर के साथ वह सम्पूर्णता की ओर बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

24.08.2018/1620/SS-YK/3

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने जो व्यक्तिगत घरों के आगे-पीछे डंगे लगाने की बात की है उसमें एकमात्र छोटा-सा सुझाव है कि उसको जहां मनरेगा में करेंगे, कुछ-न-कुछ धनराशि convergence के माध्यम से उसमें अति आवश्यक है

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2018/1625/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी----

नहीं तो वह पूरा नहीं होगा। चाहे वह सी.आर.एफ. के माध्यम से डी.सीज़ को आ जाए, कृपया आप इसको देखें।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 27 अगस्त, 2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 24 अगस्त, 2018 **सचिव ।**